शर्मा हार्डवेर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 01 | गुवाहाटी | शनिवार, 27 जुलाई, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

कारगिल में युद्ध के साथ सत्य की भी जीत हुई : पीएम पेज 2
राज्य सरकार ने एनआरएल और ऑयल इंडिया रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी... पेज 3
नौकरियों में बीसीए को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के फॉर्मूले को स्पष्ट करे ... पेज 5
भारत की झोली में पदक डालने को मेरठ की तीन बेटियां तैयार, पारुल बनाएंगी ये रिकॉर्ड पेज 7

विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ असम का मोईदाम टीला

पीएम ने गर्व व्यक्त किया • गृहमंत्री ने जताई खुशी • सीएम तथा केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने दी बधाई

नई दिल्ली (हि.स.)। असम के मोईदाम ऐतिहासिक टीला शवागार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नई दिल्ली स्थिति भारत मंडपम में आज विश्व धरोहर समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मोइदाम विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला सांस्कृतिक स्थल (सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से) और उत्तर पूर्व का तीसरा समग्र स्थल है। दो अन्य काजीरंगा और मानस हैं, जिन्हें पहले ही प्राकृतिक विरासत श्रेणी के अंतर्गत अंकित किया गया था। आज की इस घोषणा के बाद चराईदेउ मोईदाम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार एक दशक से इसे विश्व धरोहर घोषित करने की मांग कर रही थी। चराईदेउ मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिति के कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। चराइदेउ मोईदाम असम में शासन करने वाले अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी। राजा को उनकी सामग्री के साथ दफनाया जाता था। चराईदेउ मोईदाम पूर्वोत्तर भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। इन प्राचीन दफन टीलों का निर्माण 13वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम राजाओं ने कराया था। घास के टीलों जैसे दिखने वाले चराईदेउ मोईदाम को अहोम समुदाय पवित्र मानता है। प्रत्येक मोईदाम को एक अहोम शासक या

गणमान्य व्यक्ति का विश्राम स्थल माना जाता है। यहां उनके अवशेषों के साथ-साथ मूल्यवान कलाकृतियां और खजाने संरक्षित हैं। मोईदाम असमिया पहचान और विरासत की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। चराईदेउ मोईदाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के चराईदेउ मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया है। मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है। मोदी ने आगे कहा कि चराईदेउ में मोईदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जो पूर्वजों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के बारे में यूनेस्को की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए यह बहुत खुशी और गर्व की बात है! चराईदेउ में मोईदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पूर्वजों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा होती है। मुझे उम्मीद है कि अधिक लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में जानेंगे। मुझे खुशी है कि मोईदाम विश्व विरासत सूची में शामिल हो गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के चराईदेउ मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि मोईदाम अहोम राजवंश की टीला-दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। असम के चराईदेउ में शाही दफन टीले अहोम राजवंश के राजाओं और रानियों की यादें संजोए हुए हैं। यह राजवंश कई बार विशाल मुगल सेना को परास्त करने के लिए जाना जाता है। यह शिलालेख असम के इतिहास को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेगा। उधर चराइदेउ मैदाम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दिए जाने -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति

गुवाहाटी में पारा 37.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

गुवाहाटी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि असम के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति रहने की संभावना है, क्योंकि लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। गुवाहाटी में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तापमान में इस तेज वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आईएमडी ने आगे भविष्यवाणी की है कि असम में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जो 27 जुलाई तक कुछ मैदानी इलाकों में सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहेगा। दिन के समय आसमान साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा उच्च सौर विकिरण के कारण, असम में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है, जो सप्ताहांत तक राज्य के कुछ जिलों के मैदानी इलाकों में सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गुरुवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस लमडिंग में दर्ज किया गया। गुरुवार को सिलचर में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस, उदालगुड़ी में 38 डिग्री सेल्सियस, एम.मंगलदाई में 37.9 डिग्री सेल्सियस, धुबड़ी में 37.7 डिग्री सेल्सियस, डिब्रूगढ़ में 35.7 डिग्री सेल्सियस, तेजपुर में 35.7 डिग्री सेल्सियस और उत्तर लखीमपुर में 35.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार को सिलचर में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के व्दार हैं।

-कबीर

एचएनवाईएफ ने मेघालय के *पर्यटन स्थलों* में असम के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

शिलांग। हिनीवट्रेप नेशनल यूथ फेडरेशन (एचएनवाईएफ) ने शुक्रवार को असम पंजीकरण वाली पर्यटक टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें उमटिंगनगर इलाके से वापस भेज दिया। इन वाहनों को सोहरा और दावकी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की ओर जाने से रोक दिया गया। एचएनवाईएफ का यह फैसला उन आरोपों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया है कि स्थानीय वाहनों को यात्रियों को इन गंतव्यों तक ले जाने से रोका जा रहा है। संगठन ने घोषणा की है कि वह असम पंजीकरण (एएस) वाले वाहनों को इन क्षेत्रों में पर्यटकों को ले जाने की अनुमति नहीं देगा। एएस पंजीकरण वाले कई पर्यटक वाहनों को वापस भेज दिया गया। जवाब में, स्थिति का आकलन करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को इलाके में तैनात किया गया है। -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने पर रक्षामंत्री ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में देश का तीसरा रक्षा गलियारा स्थापित करने के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान सिंह से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु के बाद राज्य में रक्षा गलियारा स्थापित करने के मुद्दे पर चर्चा की। शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना के बाद हम चाहते हैं कि यह रक्षा उत्पादन केंद्र बने और सिंह ने प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है लेकिन इसकी संवेदनशीलता के कारण इसमें कुछ समय लग सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले कई कारकों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, लेकिन रक्षा गलियारा स्थापित करने से राज्य के आर्थिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। शर्मा ने यह भी कहा कि पहली बार केंद्रीय बजट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि असम की बाढ़ देश के बाहर से आने वाले पानी के कारण और भी विकराल हो गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र ने इस मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक सहायता प्रदान करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर गुवाहाटी के -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

जितनी आबादी उतना आरक्षण... रास में निजी विधेयक पेश

नई दिल्ली। पिछड़ी जातियों को आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी है। शुक्रवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने एक निजी विधेयक पेश किया। सपा सांसद का कहना है कि आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए। जावेद अली ने कहा कि 26 जुलाई का दिन आरक्षण -शेष पृष्ठ दो पर

ओबामा ने भी किया कमला हैरिस का समर्थन

नई दिल्ली (हि.स.)। डेमोक्रटिक पार्टी ऑफ अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को आखिरकार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी समर्थन प्राप्त हो गया है। इस प्रकार कमला हैरिस के राह की आखिरी अड़चन भी समाप्त हो गई है। यह तय हो गया है कि वे आगामी 8 अगस्त को डेमोक्रेट रूल्स कमेटी की तयशुदा शर्तों -शेष पृष्ठ दो पर

नेमप्लेट पर रोक जारी, एससी ने खारिज की यूपी सरकार की दलील

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कहा कि कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी करते हुए 22 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात कही। इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए अपने आदेश का बचाव किया था। सरकार ने कहा था कि उसने नेमप्लेट का आदेश इसलिए दिया था कि राज्य में शांति बनी रहे। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने कांवड़ यात्रा -शेष पृष्ठ दो पर

डिटेंशन सेंटर की दयनीय स्थिति को लेकर एससी ने असम सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम सरकार को एक डिटेंशन सेंटर की *दयनीय स्थिति* के लिए फटकार लगाई, जिसमें अस्पष्ट नागरिकता वाले व्यक्तियों और निर्वासित होने की प्रतीक्षा कर रहे विदेशियों को रखा गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह *पानी और स्वच्छता सुविधाओं की कमी और काम न करने वाले शौचालयों* से परेशान है। ग्वालपाड़ा जिले के मटिया में एक हिरासत केंद्र के बारे में असम विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि वहां न तो उचित शौचालय हैं... न ही चिकित्सा सुविधाएं। आप क्या प्रबंध कर रहे हैं? इसमें आगे कहा गया कि हमें लगता है कि सुविधाएं बहुत खराब हैं... पर्याप्त पानी की आपूर्ति -शेष पृष्ठ दो पर

विदेश मंत्रालय को ममता की नसीहत

मुझे मत सिखाओ बल्कि मेरे से सीख लो

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के शरणार्थियों को आश्रय देने की उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) पर पलटवार किया। बनर्जी ने कहा कि मैं संघीय ढांचे को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं सात बार सांसद रही, मैं दो बार केंद्रीय मंत्री रही। मैं विदेश मंत्रालय की नीति को किसी और से बेहतर जानती हूं। उन्हें मुझे सबक नहीं सिखाना चाहिए। उन्हें -शेष पृष्ठ दो पर

ओलंपिक उद्घाटन से पहले फ्रांस के हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर हमला, आगजनी, रेल यातायात ठप

पेरिस (हि.स.)। पूरे विश्व की नजरें इस समय पेरिस ओलंपिक पर लगी हुई हैं लेकिन इससे ऐन पहले फ्रांस के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क पर हमला हो गया है। उद्घाटन से कुछ घंटे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठप करने की दुर्भावना से ये हमला किया गया। पिछली रात भी फ्रांस की रेलवे कंपनी एसएनसीएफ की अटलांटिक, उत्तरी और पूर्वी हाई-स्पीड लाइनों पर कई हमले हुए। रेलवे प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई। पेरिस ओलंपिक के फ्रांस की रेलवे कंपनी एसएनसीएफ ने आज कहा कि उसके हाई स्पीड रेल नेटवर्क को पंगु बनाने के उद्देश्य से कई सारे हमले किए गए। कंपनी ने एक बयान में कहा कि टीजीवी हाई-स्पीड नेटवर्क आगजनी हमले जैसे कृत्यों से बाधित हो गया है, जिससे लगभग 8 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं और पेरिस 2024 उद्घाटन समारोह से पहले देरी हो रही है। पेरिस और लंदन के बीच यूरोस्टार ट्रेनें भी प्रभावित हुईं। कंपनी का कहना है कि टीजीवी नेटवर्क को पंगु बनाने के लिए यह बड़े पैमाने पर -शेष पृष्ठ दो पर

पापुआ न्यू गिनी में एक गिरोह ने की बच्चों समेत 26 ग्रामीणों की हत्या

मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया)। संयुक्त राष्ट्र और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी हिस्से में दूर दराज के तीन गांवों में एक गिरोह के हाथों कम से कम 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र के ईस्ट सेपिक प्रांत के कार्यवाहक प्रांतीय पुलिस कमांडर जेम्स बाउगेन ने शुक्रवार को *ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प* को बताया कि घटना बहुत भयावह थी, जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां बच्चे, पुरुष व महिलाओं की लाशें पड़ी थीं। उन्हें 30 युवकों के एक समूह ने मार डाला। बाउगेन ने एबीसी को बताया कि गांवों के सभी घर जला दिए गए हैं और शेष ग्रामीण पुलिस थाने में शरण लिए हुए हैं। बाउगेन के अनुसार, ग्रामीण हमलावरों का नाम बताने से भी डर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात में कुछ शवों को पास के दलदल के मगरमच्छों -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

कारगिल में युद्ध के साथ सत्य की भी जीत हुई : पीएम

कारगिल (हि.स.)। पच्चीसवें कारगिल विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस गवाह है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर हैं। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था। सत्य की भी जीत हुई थी। उस समय भारत शांति के लिए कार्य कर रहा था। पाकिस्तान ने विश्ववासघात किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 26 जुलाई, 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। आज लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की गवाह बन रही है। मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी प ?ी लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहस से कुछ नहीं सीखा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट किया। यह सुरंग लद्दाख को हर मौसम में संपर्कु प्रदान करेगी। इस सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब टनल भी शामिल है, जिसका निर्माण निमू-पदुम-दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा।

नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल करना चाहिए : ममता बनर्जी

नई दिल्ली। नीति आयोग की 27 जुलाई को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सरकार द्वारा लाये गए नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। बनर्जी नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगी, हालांकि *इंडिया* गठबंधन में शामिल दलों के शासन वाले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने (भाजपा ने) सरकार तो बना ली है, लेकिन उनके पास जनादेश नहीं है। 2014 के बाद भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है कि उन्होंने अकेले पार्टी के रूप में सरकार नहीं बनाई है। बनर्जी ने कहा कि अपनी *मजबूरियों* के कारण, भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने *राजनीतिक रूप से बहुत पक्षपाती बजट* पेश किया है, जिसने विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को उनके अधिकारों से *वंचित* कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि कम से कम एक साझा मंच पर इस आवाज को उठाना मेरा कर्तव्य है, हालांकि मुझे पता है कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। बनर्जी ने कहा कि जब से नीति आयोग की योजना बनी, मैंने एक भी काम होते नहीं देखा है, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। पहले योजना आयोग था। एक मुख्यमंत्री के तौर पर...उस समय मैंने देखा कि एक व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि योजना आयोग के तहत राज्य सरकारों को अपने मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार था और यह विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों का ख्याल रखने के लिहाज से बहुत अच्छा था। बनर्जी ने कहा कि लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि मैं नीति आयोग को खत्म करने के लिए आवाज उठाऊंगी। इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। वे कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए साल में एक बार बैठक करते हैं। कृपया योजना आयोग को फिर से वापस लाएं। उन्होंने कहा कि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की योजना थी और आजादी के बाद से योजना आयोग ने देश के लिए बहुत काम किया।

465 अभ्यर्थियों में सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज राज्य के 465 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र बांटे। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने युवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से रोजगार प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में 97 हजार 505 अभ्यर्थियों को नौकरियां देने के बाद आज श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के एक विशेष समारोह में विभिन्न विभागों के लिए 465 अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि वे मई 2025 तक 50 हजार अतिरिक्त नियुक्तियों को पूरा करने की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

कुंडिल नदी में लापता अन्य दो किशोरों के भी शव बरामद

तिनसुकिया (हिंस)। सदिया के पगलाम में कुंदिल नदी में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बहने से चार किशोर लापता हो गए थे। पुलिस ने दो शवों को पहले ही निकाल लिया था। शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि अन्य दोनों लापता किशोरों के शवों को भी कुंडिल नदी से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि सदिया के पगलाम में कुंदिल नदी में नहाने के दौरान चार किशोर लापता हो गए थे। अब तक चारों बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं। शुक्रवार को बरामद दोनों मृतक बच्चों की पहचान राम भट्टाराई और रोहित छेत्री के रूप में हुई है।

आरएसएस पर *प्रतिबंध* लगाने वाली सरकार को कोर्ट की फटकार

भोपाल। हाल ही में जब मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध हटाया तो सियासी बवाल खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाकर इन कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि वह संविधान नहीं बदल पा रहे हैं तो अब पिछले दरवाजे से सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस का कब्जा करवा कर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। अन्य विपक्षी दलों ने भी लगभग ऐसी ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को अब जरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को देखना चाहिए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की *खिंचाई* करते हुए कहा है कि सरकार को अपनी इस चूक का अहसास करने में करीब पांच दशक लग गए कि *राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरीखे विश्व प्रसिद्ध संगठन* को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत तरह से शामिल किया गया था। अदालत ने संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के सरकार के हालिया फैसले के हवाले से यह तल्ख टिप्पणी की। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता की रिट याचिका का निपटारा करते यह टिप्पणी की। पुरुषोत्तम गुप्ता ने 19 सितंबर 2023 को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के साथ ही केंद्र सरकार के उन कार्यालय ज्ञापनों को चुनौती दी थी जो संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने में बाधा बन रहे थे। युगल पीठ ने संघ से जुड़ने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों पर लगाई गई पाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध तभी हटाया गया जब इसे वर्तमान याचिका के माध्यम से अदालत के संज्ञान में लाया गया। अदालत ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों की पृष्ठभूमि में अलग-अलग न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारियों के *दुराचरण* को परिभाषित करते समय सरकार खुद को *सर्वेसर्वा* मानकर बर्ताव नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि बार-बार मांगे जाने के बावजूद सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण अदालत यह मानने को मजबूर है कि ऐसी कोई सामग्री, अध्ययन, सर्वेक्षण या रिपोर्ट संभवत: कभी मौजूद नहीं थी जिसके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि देश का सांप्रदायिक ताना-बाना और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बरकरार रखने के वास्ते केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की गैर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ने से रोका जाना चाहिए। पीठ ने ताकीद की कि किसी भी संगठन को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला सत्ता में बैठे लोगों की व्यक्तिपरक राय पर नहीं, बल्कि स्पष्ट तर्कों, निष्पक्षता और न्याय के नियमों पर आधारित होना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसलिए एक बार जब सरकार ने (कर्मचारियों के लिए) प्रतिबंधित संगठनों की सूची से संघ का नाम हटाने का निर्णय किया है, तो इस फैसले की निरंतरता संबंधित वक्त की सरकार की सनक, दया और खुशी भर पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। पीठ ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय को निर्देश भी दिया कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट के *होम पेज* पर नौ जुलाई के उस कार्यालय ज्ञापन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें जिसके जरिये सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाई गई है। अदालत ने इस ज्ञापन को देश भर में केंद्र सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों को 15 दिन के भीतर भेजने का निर्देश भी दिया।

पृष्ठ एक का शेष

विश्व धरोहर सूची...

के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने असम की जनता को दी बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि आज का दिन असम के लिए यादगार दिन रहेगा। हमारे चराइदेउ मैदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे चिर प्रतिक्षित उम्मीदें पूरी हो गई हैं। आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक उल्लेखनीय दिन के रूप में दर्ज रहेगा। यह असम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि चराइदेउ का मैदाम गहरी आध्यात्मिक आस्था, समृद्ध विरासत और वास्तुकला और असम के ताई-अहोम लोगों की स्थापत्य कला का प्रतीक है। आज की उपलब्धि है कि काजीरंगा और मनास राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम के संदर्भ में चराइदेउ मैदाम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। पूर्वोत्तर में एक मात्र चराइदेउ मैदाम को ही सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शानदार चराइदेउ मैदाम को इस महान उपलब्धि देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास उल्लेखनीय हैं। असम के लोगों की ओर से, मैं प्रधानमंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर एक बार असम के लोगों को ह्रदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उधर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी मान्यता है। मैं पूर्वोत्तर के लोगों की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। यह फिर से साबित करता है कि पीएम मोदी असम और उत्तर-पूर्व की सेवा करना जारी रखते हैं और परिणामस्वरूप, हमें दुनिया भर में पहचान हासिल करने का मौका मिला... मैं अहोम समुदाय और असम सरकार को भी धन्यवाद देता हूं।

गुवाहाटी में पारा 37.8...

अगले 48 घंटों के दौरान असम के कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है और उसके बाद के 48 घंटों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिम असम के जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस (1.5 से 2.5 तक), मध्य असम के जिलों में 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस (1.5 से 3.5 तक), पूर्वोत्तर असम के जिलों में 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस (1.0 से 3.0) और दक्षिण असम के जिलों में 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस (2.0 से 4.0) तक जा सकता है।

एचएनवाईएफ ने मेघालय...

अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद, एचएनवाईएफ ने असम में पंजीकृत पर्यटक वाहनों को इन पर्यटन स्थलों तक जाने की अनुमति नहीं दी। एचएनवाईएफ सदस्यों ने एमआरएसएसए के अनुसार परमिट पर तर्क दिया और सिक्किम मॉडल का हवाला दिया, जहां अन्य राज्यों से पर्यटक टैक्सियों को गंगटोक, पेलिंग और नामची से आगे जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, असम में पंजीकृत निजी वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। उल्लेखनीय है कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकार ने 2007 में पश्चिम बंगाल में पंजीकृत पर्यटक कैब को गंगटोक, पेलिंग और नामची में यात्रियों को उतारने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन पड़ोसी राज्य से पर्यटक टैक्सियों पर बंगाल सरकार की चिंताओं का जवाब देने में सिक्किम द्वारा विफल रहने के बाद 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उस समझौते को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, सिक्किम के तीन मुख्य शहरों में यात्रियों को उतारना पहले से ही एक स्थापित मानदंड है, जिसके आगे स्थानीय टैक्सियां उन्हें ले जाती हैं। हालांकि, इस साल जुलाई में पश्चिम बंगाल सरकार ने सिक्किम के वाणिज्यिक वाहनों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास विशेष परमिट नहीं था। इसी तरह बंगाल सरकार ने हिमालयी राज्य में आने वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगाया। और यह जुर्माना 3000 से 4000 रुपए प्रति वाहन है। पश्चिम बंगाल से हर दिन करीब 3000 वाहन यात्रियों को लेकर सिक्किम जाते हैं।

राज्य में देश का ...

निकट एक सैटेलाइट टाउनशिप के लिए वित्त पोषण, नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम के विस्तार और इसकी चौथी इकाई को चालू करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि आधार कार्ड का मुद्दा, जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन करने के लिए बायोमेट्रिक्स लेते समय अवरुद्ध हो गया था, जल्द ही हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 9.23 लाख आधार कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और इससे लोगों, विशेषकर छात्रों को भारी असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक के दौरान उन्होंने राम मंदिर की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए गुवाहाटी से लखनऊ तक एक विशेष ट्रेन सेवा का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य से एक लाख से अधिक तीर्थयात्री अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, लेकिन फिलहाल सीधी ट्रेन सेवा न होने के कारण उन्हें असुविधा हो रही है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही एक अधिवास नीति पेश करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य की भाषा में दक्ष स्थानीय निवासियों को भर्ती में वरीयता दी जाए। शुरुआत में, यह नीति तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर लागू होगी, जिसे समय के साथ अन्य पदों पर भी लागू करने की योजना है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने असमिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के राज्य के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रश्नपत्र असमिया में तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार शिक्षकों के लिए मौजूदा प्रणाली के समान ग्रेड 3 और 4 कर्मचारियों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, असम देश के पांच सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि विकास की यह प्रवृत्ति अगले छह से सात वर्षों तक जारी रहती है, तो असम एक अग्रणी विकसित राज्य बन जाएगा।

नेमप्लेट पर रोक ...

मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह 22 जुलाई के आदेश पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करेगी क्योंकि हमने अपने 22 जुलाई के आदेश में जो कुछ भी कहने की जरूरत थी, वह कह दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में फिर कहा कि किसी को भी नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पीठ ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उनके संबंधित निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकारों के जवाबों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल करने की अनुमति दी और मामले को 5 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के अपने निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि यह विचार पारदर्शिता लाने और संभावित भ्रम से बचने और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए था।

डिटेंशन सेंटर की ...

नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, या उचित शौचालय नहीं हैं। रिपोर्ट में चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मटिया डिटेंशन सेंटर, जिसमें 3,000 लोग बंद हैं, के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने असम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को डिटेंशन सेंटर का दौरा करने, घटिया सुविधाएं स्थापित करने और भोजन की मात्रा और गुणवत्ता तथा रसोई की स्वच्छता का आकलन करने के लिए कहा। इसने अथॉरिटी को तीन सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा। इससे पहले, न्यायालय ने केंद्र को पूर्वोत्तर राज्य के हिरासत शिविरों में बंद घोषित 17 विदेशियों को निर्वासित करने का निर्देश दिया था। इनमें से चार विदेशियों को दो साल से हिरासत में रखा गया है। निर्वासन के मुद्दे पर केंद्र ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 2023 में, असम सरकार ने गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पहचाने गए विदेशियों को हिरासत केंद्र में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। इन व्यक्तियों को या तो विदेशी न्यायाधिकरण, एक अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा विदेशी घोषित किया गया था, या अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था। अगस्त 2019 में असम ने भारतीय नागरिकों को राज्य में रहने वाले अवैध अप्रवासियों से अलग करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित किया। इसकी शर्तों के अनुसार, जो कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च, 1971 की आधी रात से पहले असम में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें नागरिक नहीं माना जा सकता।

मुझे मत सिखाओ...

इससे सीखना चाहिए। नौकरी में आरक्षण के विरोध को लेकर बांग्लादेश में हुई हिंसक झड़पों के बाद ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बात की थी। उनकी टिप्पणी कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आई, जहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की *शहीद दिवस* रैली में कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बनर्जी की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजनयिक चैनलों के माध्यम से कहा कि उनकी टिप्पणियां भ्रम पैदा कर सकती हैं और जनता को गुमराह कर सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसे ममता बनर्जी की टिप्पणी पर ढाका से एक लिखित आपत्ति मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि विदेशी संबंधों से जुड़े मामले केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। जयसवाल ने कहा कि हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची - सूची एक - संघ सूची - आइटम 10 के तहत, विदेशी मामलों का संचालन और सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है।

ओलंपिक उद्घाटन से ...

हमला किया गया है। अब कई रूट को रद्द करना होगा और मरम्मत के दौरान यह स्थिति कम से कम पूरे सप्ताहांत तक चलेगी। राष्ट्रीय ट्रेन ऑपरेटर ने कहा कि एसएनसीएफ रातोंरात एक साथ कई दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का शिकार हो गया। इन हमलों ने विशेष रूप से ग्रीष्मावकाश यात्रा के दौरान भारी यातायात के समय अटलांटिक, उत्तरी और पूर्वी लाइनों को प्रभावित किया। दक्षिण-पूर्वी लाइन प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि इधर एक दुर्भावनापूर्ण करतूत को नाकाम कर दिया गया था। आगजनी के हमले हमारी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए शुरू किए गए हैं। नतीजतन, प्रभावित लाइनों पर यातायात बुरी तरह बाधित हुआ है। एक ट्रेन ऑपरेटर के अनुसार पेरिस को पश्चिमी और उत्तरी फ्रांस से जोड़ने वाली लाइनों के साथ कई प्रतिष्ठानों में आग लग गई है और इससे काफी नुकसान हुआ है। एसएनसीएफ के मुख्य कार्यकारी जीन-पियरे फरांडो ने कहा कि हमलावरों ने कई (फाइबर-ऑप्टिक) केबल ले जाने वाले नाली में आग लगा दी थी। हमें उनकी एक-एक करके मरम्मत करनी होगी, जो एक मैनुअल ऑपरेशन है। इसमें सैकड़ों श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एसएनसीएफ ने घोषणा की है कि पेरिस के गारे मोंटपर्नासे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं होगी, जो देश के पश्चिम में दोपहर 1 बजे तक सेवा प्रदान करता है। कंपनी ने कहा कि सभी प्रभावित ग्राहकों को सभी ट्रेन टिकटों की शत प्रतिशत राशि वापस मिलेगी। कंपनी के यात्री सेवाओं के प्रमुख क्रिस्टोफ फेनिचेट ने कहा कि पेरिस और फ्रांस के उत्तर और पूर्व के बीच सेवाओं में 90 मिनट से दो घंटे की देरी हुई। कंपनी ने यह भी कहा कि सभी यात्रियों को अगले कुछ घंटों में एसएमएस और ई-मेल से सूचित किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि पेरिस और लंदन के बीच यूरोस्टार की कई ट्रेनों को भी आज रद्द कर दिया गया। यूरोस्टार ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि पेरिस से आने और आने वाली सभी हाई स्पीड ट्रेनों को आज क्लासिक लाइन के माध्यम से डायवर्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि वे एक मार्ग पर अतिरिक्त 90 मिनट लेंगे, जो आमतौर पर लगभग दो घंटे और 20 मिनट लगते हैं। यूरोस्टार ने मीडियाकर्मियों को यह भी बताया कि पेरिस और ब्रसेल्स के बीच की लाइन बाधित हो गई है। कंपनी ने कहा कि पेरिस और लंदन के बीच लगभग 25 फीसदी यूरोस्टार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यूरोस्टार ने एक बयान में कहा कि शनिवार और रविवार को भी ऐसा ही होगा। कंपनी को उम्मीद है कि सोमवार सुबह तक व्यवधान दूर हो जाएगा। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल ने कहा कि आज सुबह एसएनसीएफ के प्रतिष्ठानों के खिलाफ समन्वित और सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इससे रेल नेटवर्क पर गंभीर असर हुआ है। सिक्योरिटी सर्विसेज अपराधियों का पता लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ की घटनाओं का एक स्पष्ट उद्देश्य था: हाई-स्पीड ट्रेन नेटवर्क को अवरुद्ध करना। प्रधान मंत्री ने कहा कि समन्वित तोड़फोड़ ऑपरेशन सुबह-सुबह किया गया था। इसके परिणाम बहुत व्यापक और गंभीर हैं। दरअसल, ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं, जब पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की तैयारी कर रहा है, जिसमें 7,500 एथलीट, 3 लाख दर्शक और वीआईपी दर्शक मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि भले ही पेरिस खेलों के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले ट्रेन प्रणाली में गड़बड़ी की गई लेकिन उन्हें फ्रांस के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। जर्मनी के इस खिलाड़ी ने ओलंपिक एथलीट विलेज में मीडिया से कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है। पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने कहा कि रेल नेटवर्क में तोड़फोड़ का समारोह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जर्मन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शोजंपिंग में दो जर्मन एथलीट उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए पेरिस जाने वाली ट्रेन में थे, उन्हें काफी देरी होने के कारण बेल्जियम में वापस जाना पड़ा। वे अब समारोह में शामिल नहीं होंगे।

पापुआ न्यू गिनी में ...

ने निवाला बना लिया। हमने केवल वह जगह देखी जहां उन्हें मारा गया था। लोगों के सिर काट दिए गए थे। बाउगेन ने बताया कि हमलावर छिप गए हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त वोल्कर तुर्कु ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि हमले 16 जुलाई और 18 जुलाई को हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं पापुआ न्यू गिनी में घातक हिंसा के अचानक फैलने से भयभीत हूं। हिंसा भूमि और झील के स्वामित्व और इसके उपयोग संबंधी विवाद का परिणाम प्रतीत होती है। तुर्कु ने बताया कि कम से कम 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 16 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या बढ़ कर 50 से अधिक हो सकती है क्योंकि स्थानीय अधिकारी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा घरों को जला दिए जाने कारण 200 से अधिक ग्रामीण अन्यत्र चले गए है।

जितनी आबादी उतना ...

के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसी दिन छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने राज्य में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया था। अली ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-16 में उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। जावेद अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसद तय की है। मगर कई राज्यों की मंशा इस सीमा से अधिक आरक्षण मुहैया कराने की है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कुल 69 प्रतिशत आरक्षण है। केंद्र सरकार की ए, बी, सी और डी ग्रुप की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के कर्मियों की संख्या 27 प्रतिशत से भी कम है। सपा सांसद ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि पिछले 10 साल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी श्रेणियों में खाली पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया। उधर, कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी ने जाति आधारित जनगणना की मांग की। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया था। इसे बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। भाजपा के कुछ सदस्यों ने डांगी की टिप्पणी पर विरोध जताया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष एस फान्गनॉन कोन्याक ने दोपहर तीन बजे सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया था। शाम चार बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से शांत होने की अपील भी की। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य संजय सिंह के एक ट्वीट का जिक्र किया। इसमें संजय सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि जावेद अली खान के निजी विधेयक पर भाजपा ने हंगामा किया और सदन को स्थगित करा दिया। गोयल ने कहा कि संजय सिंह ने अपने ट्वीट के माध्यम से आसन का अपमान किया है। उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने भी संजय सिंह से अपना ट्वीट हटाने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों के खिलाफ रही है। सत्ता पक्ष के सदस्य उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं लेकिन वह ऐसी बातों से नहीं डरने वाले हैं। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मुहैया कराने की मांग की। हालांकि जावेद अली के निजी विधेयक पर चर्चा अधूरी रही।

ओबामा ने भी ...

के आधार पर पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार घोषित की जाएंगी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वयं अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल *एक्स* पर कमला हैरिस के नाम पर सहमति जताने का संदेश लिखा है। बराक ओबामा ने लिखा कि इस सप्ताह मिशेल और मैंने अपनी मित्र कमला हैरिस से बात की। हम समझते हैं कि वह अमेरिका की शानदार राष्ट्रपति सिद्ध होंगी, इसलिए अपने देश के सामने खड़ी कठिन चुनौती के बीच हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। हम उनके लिए हर वो काम करेंगे, जिससे वे नवंबर में होने वाले चुनाव में जीत सकें। हमें उम्मीद है कि आप सब भी हमारा सहयोग करेंगे। बराक ओबामा के इस ट्वीट के बाद कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से एकमात्र और सशक्त उम्मीदवार हो गई हैं और सभी आशंकाएं समाप्त हो गई हैं। दरअसल, राष्ट्रपति जो बाइडेन के पीछे हटने और उनके द्वारा ही उप राष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे करने के बाद से उन्हें पार्टी में चौतरफा समर्थन मिला। बिल और हिलेरी क्लिंटन के साथ ही नैन्सी पेलोसी ने भी उनके नाम का समर्थन कर दिया था। लोगों को बराक ओबामा के समर्थन का इंतजार था, जो उन्होंने गुरुवार को घोषित कर दिया। इस संबंध में कमला हैरिस ने स्वयं एक वीडियो कॉल अपने एक्स हैंडलपर जारी किया है, जिसमें बराक ओबामा उन्हें फोन कर उनका समर्थन करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए हैं। इस दृष्टि से भी कमला को उनका समर्थन खासा महत्व रखता है। यदि नवंबर में होने वाले चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प को हराकर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वे अमेरिका कि पहली महिला, पहली अश्वेत महिला और दक्षिण एशियाई मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी। कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद से ट्रम्प को मिल रही बढ़त रुक सी गई है, बल्कि पापुलर वोट में कमला हैरिस थोड़ा आगे ही बढ़ती नजर आ रही हैं।

राज्य सरकार ने एनआरएल और ऑयल इंडिया रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ किया समझौता

गुवाहाटी (हिंस)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने शुक्रवार को लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की मौजूदगी में ऑयल इंडिया रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, दुलियाजान और नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता के तहत उन्नत किडनी फेलियर रोगियों के ईलाज के लिए हेमो-डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए सीएसआर फंड के हिस्से के रूप में प्रत्येक को 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डायलिसिस केंद्रों में नई हेमो डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी। समझौता ज्ञापन का

उद्देश्य डायलिसिस मशीनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना और वर्तमान में नेफ्रोलॉजिकल बीमारियों के ईलाज के लिए मरीजों की जेब से होने वाले खर्च को कम करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित 277 एचडी मशीनों के साथ 41 डायलिसिस केंद्रों में मुफ्त हीमो-डायलिसिस सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा, बढ़ती मांग को देखते हुए, राज्य भर में 150 हीमो-डायलिसिस मशीनों के साथ 37 नए अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर आयुक्त और सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. पी अशोक बाबू, मिशन निदेशक एनएचएम असम डॉ. एमएस लक्ष्मी प्रिया, एमडी एनआरएल भास्कर ज्योति फूकन, सीजीएम एनआरएल काजल सैकिया, ऑयल इंडिया ग्रामीण विकास सोसाइटी के अध्यक्ष भैरब भुइयां, सीजीएम प्रशासन पाइपलाइन मुख्यालय अरुणज्योति बरुवा और असम सरकार, एनआरएल और ओआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डकैतों ने की एक व्यक्ति की हत्या

बंगाईगांव (हिंस)। बंगाईगांव जिले के अभयापुरी इलाके में डकैतों का एक दल घर में प्रवेश कर एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर घटना स्थल से फरार हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि बीती रात अभयापुरी के पीराधरा इलाके में स्थित कृष्णा मंडल के घर में डकैतों का एक दल प्रवेश कर सोने चांदी के गने के अलावा नगद एक दाख रुपए लूट लिए। इस दौरान डकैतों ने कृष्णा मंडल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डकैत घटना को अंजाम देकर बाहर से घर का दरवाजा बंद कर मौके से फरार होने में सफल रहे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक मोहनलाल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सविता दास समेत पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचीं। पुलिस मृत व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

मनाह नेशनल पार्क में मिला काला तेंदुआ का शव

बक्सा (हिंस)। मनाह नेशनल पार्क के बांहबाड़ी रेंज के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक नाबालिग काला तेंदुआ का शव बरामद हुआ है। शुक्रवार को वन कर्मियों ने बताया कि लोगों की सूचना पर मनाह से वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और काला तेंदुआ के शव को बरामद किया। उन्होंने कहा कि काला तेंदुआ की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

बाइक चोरी मामले में एक गिरफ्तार, एक फरार

नगांव (हिंस)। नगांव जिले के सामागुड़ी रंगागढ़ इलाके से बाइक चोरी मामले में पुलिस ने चोरी की बाइक समेत एक चोर को गिरफ्तार किया है । पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि सामागुड़ी रंगागढ़ इलाके में स्थित पत्रकार नवजीत बरुवा के घर से दो चोर बाइक (एएस-02एएफ-9201) चुरा कर बुधवार की सुबह फरार हो गए थे। घटना के संबंध में पत्रकार द्वारा स्थानीय थाने में कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाइक चोरी मामले में सामागुड़ी बरबालीटोप के बिश्वजीत बर्मन नामक एक चोर को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि बाइक चोरी मामले में शामिल मास्टरमाइंड रहमत अली अभी भी फरार है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर फरार बाइक चोर की तलाश कर रही है।

अगस्त के पहले सप्ताह में होगी भाजपा की बर्धित कार्यकारिणी बैठक : भबेश कलिता

गुवाहाटी (हिंस)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भबेश कलिता ने कहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में भाजपा की बर्धित कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भाजपा कार्यकारिणी को आगे बढ़ा दिया गया था। उपचुनाव को लेकर कार्यकारिणी में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दो राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। असम के नए प्रभारी हरीश द्विवेदी का अध्यक्ष कलिता ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि असम के मोर्चों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिद्धांकू अंकुर बरुवा को भाजपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में यूपीपीसीएल सिदली में, अगप बंगाईगांव में तथा सामागुरी, धलाई और बिहाली में भाजपा उपचुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पांच मंत्रियों को पांचों निर्वाचन क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है मंत्री पीयूष हजारिका बिहाली के प्रभारी होंगे। जबकि, मंत्री बिमल बोरा सामागुड़ी के प्रभारी, अशोक सिंघल सिदली के प्रभारी, जयंत मल्लबरुवा धलाई के प्रभारी तथा रंजीत कुमार दास बंगाईगांव के प्रभारी होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष भबेश कलिता ने कहा कि अरुणोदय के लिए लाखों महिलाओं ने आवेदन किया है। छात्राओं ने निजुत मईना योजना के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस झूठी बातें कहकर वोट लेना चाहती है।

असम का टांगला स्टेशन 14.14 करोड़ रुपए से होगा पुनर्विकसित

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर और असम में रेल सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचना वाली परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट इस चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10, 369 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत पूर्वोत्तर में 60 स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। चयनित रेलवे स्टेशनों में असम के टांगला रेलवे स्टेशन को 14.14 करोड़ रुपए आवंटित हुए है। इससे स्टेशन को नया स्वरूप मिलेगा। इस स्टेशन के नवीनीकरण से आसपास के क्षेत्रों के रेल उपयोगकर्ताओं को नवीन अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) के सीपीआरओ सव्यसाची दे शुक्रवार को बताया है कि टंगला रेलवे स्टेशन, पूसीरे के रंगिया मंडल के अधीन रंगिया-रंगापाड़ा सेक्शन के मध्य उदालगुड़ी जिले का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। उन्नत अग्रभाग के साथ इस स्टेशन भवन का विस्तार किया जाएगा, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए नवीनतम सुख-सुविधाओं के साथ रिटायरिंग रूम एवं प्रतीक्षालय की व्यवस्था रहेगी। दिव्यांगजन अनुकूल रैंप एवं शौचालय की सुविधा के साथ अन्य आधुनिक सुविधाएं जैसे दो लिफ्ट और 5 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नए शौचालय ब्लॉक पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग-अलग बनाए जाएंगे। सर्कुलेटिंग क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ उन्नत पार्किंग सुविधा की भी योजना है। सभी प्लेटफार्मों पर यात्रियों की आसान आवाजाही के लिए मार्बल स्टोन, टाइल आदि से सतह का पुनर्निर्माण किया जाएगा और शेल्टर की सुविधा रहेगी। प्रवेश निकास पथ विकसित किया जाएगा। उन्होंने बतायाकि उपरोक्त सभी कार्यों के लिए टेंडर जारी हो चुका है। नए स्टेशन भवन के लिए नींव का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अन्य यात्री सुविधाओं जैसे कोच गाइडेंस बोर्ड, ट्रेन सूचना डिस्प्ले सिस्टम की स्थापना, प्लेटफार्मों का विस्तार, दिव्यांगजनों के लिए आसान पहुंच वाले वॉटर बूथ की व्यवस्था आदि का भी कार्य प्रगति पर है।

कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित

गुवाहाटी (हिंस)। प्रथम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सोनपुर द्वारा आज वाहिनी मुख्यालय में *कारगिल विजय दिवस* के अवसर पर एएसजीआई हॉस्पिटल, गुवाहाटी के सहयोग से मुफ्त नेत्र जांच और परामर्श का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर का आयोजन प्रथम वाहिनी के कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में किया गया। सहायक कमांडेंट (एमओ) डॉ. निरजंता देवी ने नेत्र जांच शिविर आयोजित करने की पहल की। नवीनतम तकनीकी उपकरणों से स्थानीय ग्रामीण, एसएसबी कर्मी और उनके परिवार के सदस्य इस शिविर से लाभान्वित हुए।

एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के तहत *एकल कंप्यूटर लैब* कार्यक्रम का उद्घाटन

गुवाहाटी। एकल अभियान के आयाम एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा उत्तर पूर्वी प्रभाग की तीसरी एकल आन ह्वील (मोबाइल कंप्यूटर लैब) का उद्घाटन पश्चिम उत्तर पूर्वी संभाग के कोकराझाड़ अंचल में किया गया। एकल अभियान द्वारा संचालित एकल विद्यालय के गांवों में एकल कंप्यूटर लैब के माध्यम से गांवों और पिछड़े आदिवासी समुदायों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों और छात्रों को शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक विकास और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के पटेल परिवार के सहयोग से मोबाइल सौर ऊर्जा संचालित कंप्यूटर लैब की व्यवस्था

की गई है। ये मोबाइल कंप्यूटर लैब एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा पूरे भारत और असम में गांवों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाए जाते हैं ताकि पिछड़े ग्रामीण गांवों के छात्र और बच्चे कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें और भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। उत्तर पूर्व में तीसरी एकल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन 20 जुलाई को कोकराझाड़ क्षेत्र के कचुगांव संच में जलेश्वरी एलपी स्कूल परिसर में किया गया। गौरतलब है कि एक लैब में एक साथ 18 छात्र कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर लैब के अलावा, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा गोलाघाट और गोगामुख में स्थायी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, नाहरकटिया, गेलापुखुरी, गोलाघाट, रेंगमा, नावजान, कोकराझाड़ जिले के नबीन नगर और जलेश्वरी गांवों में महिला सशक्तिकरण के लिए स्थायी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र संचालित करता है। इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुकी हैं। एकल अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभारी पवन कुमार अग्रवाल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करते हुए आशा व्यक्त की की आने वाले दिनों में हम ऐसे मोबाइल कंप्यूटर लैब अन्य स्थानों के लिए भी उपलब्ध करवा पाएंगे। पूर्वोत्तर प्रभाग के अध्यक्ष अमल वैश्य, एकल ग्रामोत्थान पूर्वोत्तर की सदस्य रीना भौमिक, कोकराझाड़ अंचल के अध्यक्ष किशन लाल नाहटा, अभियान के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

आईआईई ने कृषि उद्यमिता और संधारणीय विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया

गुवाहाटी। भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) गुवाहाटी ने आज संधारणीय विकास और नवाचार बीज क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को सशक्त बनाना शीर्षक से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की। आईआईई, गुवाहाटी के निदेशक डॉ. ललित शर्मा द्वारा उद्घाटन किए गए इस संगोष्ठी में भारत के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए देश भर के शिक्षाविदों, विद्वानों और चिकित्सकों को एक साथ लाया गया। संगोष्ठी में परिशुद्ध कृषि और डेटा एनालिटिक्स जैसे अभिनव दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया, जो फसल की पैदावार और संसाधन दक्षता को अनुकूलित करते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पाद की गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार के लिए विविधीकरण और मूल्य संवर्धन रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। प्रभावी बाजार अभिविन्यास यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उद्यमी उपभोक्ता की मांगों को पूरा करें, जबकि मजबूत जोखिम प्रबंधन रणनीतियां क्षेत्र में अनिश्चितताओं को संबोधित करती हैं। संगोष्ठी का मुख्य केंद्रबिंदु पर्यावरणीय

स्थिरता का महत्व और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने वाली प्रथाओं की आवश्यकता थी। कृषि उद्यमिता उद्यमों की सफलता के लिए हितधारकों और सहायक सरकारी नीतियों के साथ सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। संगोष्ठी में विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत दस व्यावहारिक शोधपत्र शामिल थे, जिसमें कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति रूपरेखा विकसित करने में इन संस्थानों की भूमिका पर चर्चा की गई थी। चर्चाओं में कृषि उद्यमिता में अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और परिचालन में निरंतर सुधार करने के लिए आवश्यक उद्यमशील मानसिकता को रेखांकित किया गया।

गृहस्वामी की हत्या कर बदमाशों ने जेवर व नकदी लूटी

बंगाईगांव (हिंस)। बंगाईगांव जिले के अभयापुरी में बदमाशों ने शुक्रवार को तड़के एक गृहस्वामी की हत्या कर घर से सोना-चांदी समेत एक लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि शुक्रवार तड़के अभयापुरी में पीराधारा में कुछ बदमाश एक मकान में घुस गए और गृहस्वामी कृष्ण मंडल की धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। मृतक की पत्नी के मुताबिक बदमाशों ने जाते समय घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक मोहन लाल मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सविता दास ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

सबसे तेजी से विकास करने वाले शीर्ष 5 राज्यों की श्रेणी में असम : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले शीर्ष पांच राज्यों की श्रेणी में असम आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में राज्य का बैंक जमा 1.71 लाख करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 2.24 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार तीन वर्षों के भीतर बैंकों में जमा राशि में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो एक बड़े आर्थिक विकास का सूचक है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में बैंकों ने 80 हजार 871 करोड़ रुपए का असम को ऋण दिया था। जबकि, वर्ष 2024 में यह बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम का पारंपरिक क्रेडिट/डिपॉजिट अनुपात 32 प्रतिशत था, जो अब यह 58 प्रतिशत हो गया है। बेरोजगारी दर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 6.1 प्रतिशत रह गई है।

कोकराझाड़ : अवैध रूप से ले जा रहे लकड़ी को एसएसबी ने किया जब्त

कोकराझाड़ (विभास)। दिनांक 26.07.2024 को छठीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, रानीगुली के बाह्य सीमा चौकी नहारानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भारत-भूटान पिलर संख्या-154 से लगभग 8 किलोमीटर भारत की ओर सीमा चौकी नहारानी व वन विभाग उल्टापानी की संयुक्त टीम के द्वारा निजामगुड़ी गांव के पास वन क्षेत्र में गश्ती के दौरान अवैध रूप से कटे हुए इमारती लड़कियों को ले जा रहे वन माफियों को देख कर एसएसबी व फॉरेस्ट की टीम ने उनका पीछा किया, अपनी ओर आ रहे एसएसबी की टीम को देखते

ही वन माफियों ने लगभग 34.78 सीएफटी इमारती लड़कियों को जगंल मे छोड़कर भाग गए। तदोपरांत उनकी खोज टीम द्वारा की गई परंतु वे भागने में सफल हुए। कटी हुई इमारती लकड़ी को जब्त कर वन विभाग उल्टापानी को अग्रिम कार्यवाही हेतू सूपुर्द कर दिया गया। छठीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल लगातार भारत-भूटान सीमा पर भारतीय वन क्षेत्रों में गस्ती एवं चौकसी के कारण तस्करों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है।

हेपेटाइटिस ए के जोखिम को कम करे : एक टीके की खुराक की शक्ति

गुवाहाटी। संक्रामक रोगों के खिलाफ चल रही लड़ाई में, टीकाकरण सबसे प्रभावी और आवश्यक उपकरणों में से एक है। रोगजनकों को पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके, टीके संक्रमण के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले साल, उत्तरी गुवाहाटी के अमीनगांव क्षेत्र में पीने के पानी के स्रोतों के बड़े पैमाने पर सीवेज प्रदूषण के कारण हेपेटाइटिस ए का एक बड़ा प्रकोप हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप दो सप्ताह की अवधि में चार मौतें हुईं। गहन निरीक्षण से पता चला कि अधिकांश घरों में शौचालयों से जुड़े भूमिगत कक्षों में कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, जिसके कारण भूजल दूषित हो गया और सुरक्षित पेयजल की कमी हो गई। समस्या और बढ़ गई, ब्रह्मपुत्र नदी से अनुपचारित पानी की आपूर्ति की गई, और अधिकांश घरों में स्वच्छता निपटान प्रणालियां

टूट गईं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस (एचएवी) के कारण होता है, एक अत्यधिक संक्रामक लिवर संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्तियों के मल के माध्यम से फैलता है, जो गंभीर बीमारी का कारण बनता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छता और जल आपूर्ति प्रणालियों से समझौता किया जाता है। मानसून की शुरुआत से खतरा और बढ़ जाता है। हॉस्टलर्स और उन लोगों में जोखिम और भी अधिक है जो अक्सर बाहर खाना खाते हैं। बुखार, थकान, मतली, पेट की परेशानी और पीलिया के लक्षण, हेपेटाइटिस ए संक्रमण के परिणामस्वरूप गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लिवर की शिथिलता और गुर्दे की जटिलताएं हो सकती हैं, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य और भलाई प्रभावित हो सकती है। हाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के सामने, एक-शॉट हेपेटाइटिस ए टीका समुदायों को इस अत्यधिक संक्रामक लिवर संक्रमण से बचाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। जैसा कि सेंट्रल नर्सिंग होम, गुवाहाटी के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और वैक्सीन विशेषज्ञ डॉ. सीएस भट्टाचार्य कहते हैं, एक-शॉट हेपेटाइटिस ए का टीका बचाव का एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधन है। एक एकल खुराक वायरस के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती है, जो इसे कमजोर क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों का एक प्रमुख तत्व बनाती है। कई टीकों के विपरीत, जिनके लिए कई खुराक की आवश्यकता होती है, एक-शॉट हेपेटाइटिस ए का टीका सुविधाजनक और अत्यधिक प्रभावी है। 12 महीने या उसके बाद प्रत्येक बच्चे को टीका लगाना महत्वपूर्ण है और छूट जाने पर अपने बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। इसके अलावा, हेपेटाइटिस ए संक्रमण को रोकने के लिए, पीने और खाना पकाने के लिए उपचारित या उबला हुआ पानी का उपयोग करना आवश्यक है। अच्छी स्वच्छता आदतें, जैसे साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोना, खासकर शौचालय का उपयोग करने के बाद और भोजन संभालने से पहले, महत्वपूर्ण हैं। उचित सीवेज निपटान सुनिश्चित करके और स्वच्छ शौचालय सुविधाओं को बनाए रखकर स्वच्छता में सुधार से हेपेटाइटिस ए वायरस (एचएवी) के प्रसार को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

संपादकीय

केंद्रीय बजट के हाशिए

अमूमन केंद्रीय बजट की धाक पर राज्य की मिन्नतें या डबल इंजन सरकार के चरित्र में नए पोशाक की अभिलाषा रहती है, लेकिन हिमाचल ने फिर राजनीतिक पाप कर लिए। कम से कम यह तो महसूस नहीं हुआ कि हिमाचल ने अपने चारों सांसदों को केंद्र की गठबंधन सरकार को सौंप दिया है। बजट की सारी शेखियां और उम्मीदें गठबंधन धर्म में शरीक होकर आंध्र और बिहार की तश्तरियों में जो परोस रही हैं, वह कहां सामान्य तौर पर हमें मिलेगा। अचानक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट की धाराओं ने शहद में भीगना सीख लिया, जबकि पंजाब पुनर्गठन के कानूनी अधिकार आज भी हिमाचल की अर्थव्यवस्था को गौण कर रहे हैं। बजट पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और मुलाकातों के केंद्रबिंदु में रखे गए सारे तर्क पुनः पस्त हो गए। वहां हिमाचल का पानी, हिमाचल की जवानी नहीं, बल्कि पर्यावरण व देश के प्रति वफादारी भी पूरी तरह नजरअंदाज हुई है। यह दीगर है कि कहने को हिमाचल का नाम बजट की आपदा में लिपट कर आ गया, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि पिछले नुक्सान के नए मजमून दुरुस्त होंगे। सहायता के आश्वासन और भी ढूंढे जा सकते हैं, जहां केंद्रीय योजनाओं में आबंटन होगा। मसलन कृषि, जनजातीय गांव, वैकल्पिक ऊर्जा, आवासीय व्यवस्था और सौ साप्ताहिक हाट में कुछ तो रहा होगा, लेकिन केंद्रीय आश्वासन में पर्यटन जैसा क्षेत्र हिमाचल के लिए खामोश है। जाहिर है गठबंधन के प्रेम में बिहार का पर्यटन जीत रहा है, वरना कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की फाइल पर केंद्र सरकार का हाथ दिखाई देता। सरकार इस परियोजना के भू-अधिग्रहण के लिए केंद्र से 3500 करोड़ की फरियाद कर रही है, लेकिन खामोशियां अटूट बाधाएं बनकर तनी हैं। पर्वतीय राज्यों की आर्थिक विडंबनाओं तथा अति वन भूमि के अनुपयोगी आवरण के कारण जो आवश्यक, उदार व वांछित सहायता मिलती रही है, उस पर अब वित्तायोग की कुंडलियां सख्त होती जा रही हैं। नतीजतन हिमाचल पर कर्ज बोझ का भयावह आंकड़ा एक लाख करोड़ छूने को आतुर है। प्रदेश हरित राज्य बनने की कोशिश में पिछले एक साल से प्रयासरत है, लेकिन केंद्र के मोहल्ले में हमारे ये कदम पहुंच नहीं पा रहे। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सस्ती दरों पर ऋण या पर्यावरणीय सुरक्षा के एवज में ग्रांट मिलती तो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्तियों का समाधान भी निकल आता। प्रदेश सौर ऊर्जा के बड़े प्लांट व रूफटॉप सोलर एनर्जी के विकल्प में आगे बढना चाहता है, लेकिन यह हसरत केंद्र की मदद से ही पूरी होगी। जगत प्रकाश नड्डा के विभाग और अनुराग ठाकुर के प्रचार से निकली कई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं की राह पर अभी अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। खास तौर पर ऊना-हमीरपुर रेल परियोजना के ढोलक अब तक के तमाम बजटों की तरह, इस बार भी उदास हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति का सही-सही मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र पर्वतीय विकास मंत्रालय की आवश्यकता के पैरोकार ही पैदा नहीं हुए और हम सियासत के किनारे बनकर भी डूबते रहे भ्रम के समुद्र में। कहने को प्रधानमंत्रियों के साथ हमारे दिल के रिश्ते रहे हैं, लेकिन केवल एक बार औद्योगिक पैकेज के अदाकार अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कभी सपने साकार नहीं हुए। एक अदद कनेक्टिविटी या पर्यटन पैकेज से हिमाचल अपने आर्थिक जख्म ठीक कर सकता था, लेकिन इस बार तो कहने को भी कोई आशा नहीं। यह दीगर है कि मध्यमवर्गीय हिमाचल आयकर के नए फार्मूले में कोई सुकून ढूंढ ले या इंटर्नशिप के लिफाफे को देखकर पढ़ा-लिखा बेरोजगार लाभार्थी बन जाए।

डबल इंजन सरकार के चरित्र में नए पोशाक की अभिलाषा रहती है, लेकिन हिमाचल ने फिर राजनीतिक पाप कर लिए। कम से कम यह तो महसूस नहीं हुआ कि हिमाचल ने अपने चारों सांसदों को केंद्र की गठबंधन सरकार को सौंप दिया है। बजट की सारी शेखियां और उम्मीदें गठबंधन धर्म में शरीक होकर आंध्र और बिहार की तश्तरियों में जो परोस रही हैं, वह कहां सामान्य तौर पर हमें मिलेगा। अचानक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट की धाराओं ने शहद में भीगना सीख लिया, जबकि पंजाब पुनर्गठन के कानूनी अधिकार आज भी हिमाचल की अर्थव्यवस्था को गौण कर रहे हैं। बजट पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और मुलाकातों के केंद्रबिंदु में रखे गए सारे तर्क पुनः पस्त हो गए। वहां हिमाचल का पानी, हिमाचल की जवानी नहीं, बल्कि पर्यावरण व देश के प्रति वफादारी भी पूरी तरह नजरअंदाज हुई है। यह दीगर है कि कहने को हिमाचल का नाम बजट की आपदा में लिपट कर आ गया, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि पिछले नुक्सान के नए मजमून दुरुस्त होंगे।

दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी इस तरह के गहरे संबंध को खत्म करने में असमर्थ रहे हैं

लोकतंत्र और राजनीतिक हिंसा

डा. वरिंदर भाटिया J

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा का उमड़ता प्रभाव पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर के मुताबिक लोकतंत्र और हिंसा का अपवित्र और गहन संबंध है।

प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के नेताओं ने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा का उमड़ता प्रभाव पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर के मुताबिक लोकतंत्र और हिंसा का अपवित्र और गहन संबंध है। यहां तक कि दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी इस तरह के गहरे संबंध को खत्म करने में असमर्थ रहे हैं। उदाहरण के लिए 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में चरमपंथी समूहों की ओर से राजनीतिक हिंसा का विस्फोट देखा गया। हाल के वर्षों में, दुनिया ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) में ब्रेक्सिट मुद्दे, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और 2020 और 2024 के अमरीकी चुनावों पर राजनीतिक हिंसा की घटनाएं देखी हैं। भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी राजनीतिक हिंसा से कभी अलग नहीं रहा है। जहां तक देशी लोकतंत्र के राजनीतिक कटु सत्य का सवाल है तो भारत में लोकतांत्रिक शासन की जो प्रणाली विकसित हुई है, चाहे कोई माने या न माने, वह अब सेवा की बजाय सत्ता और शक्ति केंद्रित हो गई है। पश्चिम के विकसित देशों में जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करने के लिए चुने जाते हैं, जबकि भारत में लोगों पर शासन करने के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं।

चुनाव जीतने पर मिलने वाली असीमित सत्ता और पैसा समूची राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया को किसी न किसी रूप में भ्रष्ट और हिंसक बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में हिंसक राजनीतिक संघर्ष अक्सर देखने को मिलते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था कमाल की है। आज भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था के उपलब्ध तरीकों में से एक बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह बुनियादी मानवीय मूल्यों के आधार पर पनपता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जवाबदेही के साथ समाज के हित में समाज के साथ मिलकर निर्णय लेना और उन्हें लागू करना। वैसे तो देश चलाने के लिए कई

तरह की व्यवस्थाओं के विकल्प मौजूद रहे हैं, लेकिन उन सबमें लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था माना गया है, क्योंकि इस व्यवस्था में अलग-अलग विचारों, मतों, परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निर्णय लिए और लागू किए जाते हैं। यह केवल संख्याओं या बहुमत से चलने वाली व्यवस्था नहीं है। बहुमत के निर्णय को लागू करने से पहले यह देखना होता है कि व्यापक समाज के हित में क्या है? कहीं इससे अन्याय तो नहीं हो रहा है? कहीं किसी के साथ भेदभाव या शोषण तो नहीं हो रहा है? याद रहे कि लोकतंत्र में मूल्यों, उसूलों, मानकों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर बहुमत वाली व्यवस्था मूल्यों से भटक कर निर्णय लेने लगे, तो परिवार, समाज और देश को बहुत नुकसान पहुंचता है। लोकतांत्रिक समाज ज्यादा गहरा और स्थिर होता है। अगर कभी देश के ऊपर कोई संकट आता है, तब लोकतांत्रिक समाज इससे निपटने का काम केवल सरकार पर नहीं छोड़ देता है, बल्कि लोग खुद भी समाधान खोजने में जुट जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की मौजूदगी का एक बड़ा कारण संवादहीनता भी है। लोकतंत्र की पहली और सबसे बड़ी जरूरत संवाद है। यह एक ऐसा भावनात्मक तत्व होता है, जो लोगों को जोड़ता है। संवाद से ही एक-दूसरे के प्रति स्वीकार्यता पैदा होती है। जब भी लोकतंत्र को तोडना होता है, तब सबसे पहले संवाद को तोड़ा जाता है। कोई भी व्यक्ति जब अपना मत व्यक्त करता है, तब हिंसा से, डर से, भय से, दबाव से उसे अपना मत वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

यही राजनीतिक हिंसा का मूल तत्व होता है। आज अमरीकी लोकतंत्र को लेकर हमारी सोच सवालिया निशान लगा रही है। असल में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला अमरीका में नफरत की बुनियाद पर बनाए जा रहे अमरीकी समाज की भयानक तस्वीर है। एक ताजा अमरीकन सर्वे में पाया गया कि 10 प्रतिशत लोग बल प्रयोग के जरिए भी ट्रंप को रास्ते से हटाने के पक्षधर हैं, तो 7 प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जो हर ताकत का इस्तेमाल कर ट्रंप को सत्ता में लाने के समर्थक हैं। यह रस्साकशी भी वहां राजनीतिक हिंसा के लिए एक कारक हो सकती है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, जो शिकागो प्रोजेक्ट ऑन सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स के डायरेक्टर भी हैं, ने नेशनल सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 10 प्रतिशत अमरीकी वयस्क नागरिक, जिनमें से एक-तिहाई के पास बंदूकें हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि 'डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए बल का प्रयोग उचित है।' लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की मौजूदगी किसी भी शासकीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। भारत में हो रही पॉलिटिकल किलिंग्स की संख्या चिंताजनक है। देश में 2017 से 2019 के बीच, यानी महज दो साल के भीतर करीब 230 हत्याएं राजनीतिक कारणों से हुईं। इनमें सबसे अधिक 49 हत्याएं झारखंड में हुईं। इसके बाद 27 हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुईं और 26 हत्याएं बिहार में हुईं। ये आंकड़े सरकार ने लोकसभा में रखे थे। केरल में भी राजनीतिक हत्याओं के खूब मामले सामने आए हैं। 2006 से 2021 के बीच 125 पॉलिटिकल मर्डर हुए। इनमें से 30 मर्डर तो 2016 से 2021 के बीच ही हो गए। पश्चिम बंगाल में भी बीते कई सालों से स्थिति चिंताजनक है। पूरे विश्व में राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए राजनेताओं को आगे आना होगा। मीडिया की शिक्षा में 'टू स्टेप फलो मॉडल' नाम की थ्योरी पढ़ाई जाती है। इस थ्योरी में कहा गया है, 'मास मीडिया के मुकाबले लोग ओपिनियन लीडर्स (नेता) की बातों से प्रभावित होते हैं।' इसलिए राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए यह भी कहना जरूरी है कि विश्व के समस्त राजनेता संयम के साथ शब्दों का इस्तेमाल करें। राजनीतिक हिंसा के व्यक्तियों, समुदायों और समाजों पर दूरगामी परिणाम होते हैं।

दृष्टि कोण

जब कारगिल जंग में बेनकाब हुआ पाकिस्तान...

कारगिल के महाज पर आग उगलने में कुख्यात बोफोर्स तोपों की शदीद बमबारी तथा भारतीय सेना द्वारा पाक सेना की बेरहमी से हलाकत से पाकिस्तान की 'नार्दर्न लाइट इन्फैंट्री' का वजूद लगभग खल्लास होने वाला था। उस वक्त पाक जरनैलों ने अपनी आबरू बचाने के लिए वजीरे आजम नवाज शरीफ को अमन का पैरोकार बनाकर अमरीका, ब्रिटेन, चीन व तुर्की जैसे मुल्कों की कदमबोसी करने पर मजबूर कर दिया था। परंतु कारगिल घुसपैठ में किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की थी। बैरूने मुल्कों से बेआबरू होकर लौटे नवाज शरीफ ने 12 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की आवाम से खिताब किया और फरमाया कि 'हम कब तक अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेचकर तोपों के गोले बनाते रहेंगे'। मगर दौरान-ए-तकरीर में नवाज शरीफ ने अपनी आवाम को कारगिल मंसूबे की हकीकत से महरूम रखा। कारगिल की जंग में जांवाहक हो रहे पाक सैनिकों को मुजाहीद्दीन करार दे दिया था। कारगिल जंग की हकीकत तथा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्तूबर 1999 को तख्तापलट को अंजाम देकर पाकिस्तान में फौजी हुकूमत नाफिज कर दी। सेना के आगे नवाज शरीफ ने इक्तदार से अलग होने में ही आफियत समझी। कारगिल में पाक सेना की घुसपैठ करवाकर भारत को दहलाने के मंसूबे के सूत्रधार परवेज मुशर्रफ फरवरी 2023 को कश्मीर हथियाने की अधूरी ख्वाहिश के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरहूम सिपाहसालार के लिए सुखद एहसास यह रहा कि इंतकाल के बाद उनकी मय्यत को पाकिस्तान का कब्रिस्तान नसीब हो गया, मगर जरनैल रहते जिन पाक सैनिकों को कारगिल जंग की आग में झोंक दिया था, वो बदनसीब थे, जिनकी मय्यत को न उनके वतन की मिट्टी नसीब हुई और न ही ताबूतों पर पाकिस्तान का परचम चस्पां हुआ। परवेज मुशर्रफ, अजीज खान, महमूद अहमद व जावेद हसन चारों पाक जरनैल कारगिल के मंसूबे को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने वाले प्रमुख चेहरे थे। एलओसी पर घुसपैठ की जिम्मेदारी 'स्पेशल आपरेशन डिवीजन' के सरवराह मेजर जनरल 'अशरफ रशीद' को दी गई थी। कारगिल जंग में पाक सैनिकों की दर्दनाक हलाकत व शर्मनाक शिकस्त से जलील होकर घुसपैठ के अहम किरदार अशरफ रशीद ने सितंबर 1999 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कारगिल जंग में हलाक हुए पाक सैनिकों की लाशें उठाने का जिम्मा '12 एनएलआई' के कर्नल 'खालिद नजीर' व फ्रंटियर फोर्स के कर्नल 'मुस्तफा' को सौंपा गया था। परंतु जंग में पाक फौज के किरदार पर पर्दा डालने के लिए हलाक हुए पाक सैनिकों की लाशें बरामद करने में पाकिस्तान ने शिद्दत नहीं दिखाई। उन मरहूम पाक सैनिकों के परिवारजन आज भी इंतजार में हैं, लेकिन अपनी जान का नजराना पेश करने वाले दुश्मन सैनिकों को भारतीय सेना ने मैदाने जंग में खिराज-ए-अकीदत पेश करके आदमियत की मिसाल कायम की थी। 29 मई 1999 को कारगिल क्षेत्र में भारतीय सेना के जोरदार हमले में अपने पूरे सैन्य दल के साथ हलाक हुए 'तीन एनएलआई' के कैप्टन 'इनाम उल्लाह' 'तगमा-ए-बसालत' को पाक सेना ने कारगिल जंग में अपना प्रथम शहीद सैन्य अफसर माना था। भारतीय सेना ने इनाम उल्लाह की लाश के अवशेष पाकिस्तान को लौटाए थे। नौ जून 1999 को भारतीय सेना ने कैप्टन 'फरहत हसीब' 'सितारा-ए-जुर्रत' को उसके सैन्य दस्ते के साथ हलाक करके कारगिल के मोर्चे पर ही दफन कर दिया था। 27 जून 1999 को सेना की 'राजपूत रेजिमेंट' ने 'तुर्तुक सेक्टर' में बिलाल पोस्ट पर हमला करके कैप्टन 'तैमूर मलिक' सहित ग्यारह पाक सैनिकों को हलाक कर दिया था। तैमूर का शव प्राप्त करने के लिए उसके परिजनों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से सिफारिश की थी। शहादत के कई दिनों बाद भारतीय सेना ने तैमूर मलिक 'तगमा-ए-बसालत' का शव पाकिस्तान को सौंपा, तो पाक सेना के तर्जुमान तौकिर जिया ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया था। चार जुलाई 1999 को टाइगर हिल के मोर्चे पर कैप्टन अम्मार हुसैन, मेजर अरशद हाशिम व दर्जनों पाक सैनिकों को हलाक करके भारतीय सेना ने वहीं सपुर्दे-खाक करके तहज्जुद की नमाज अदा कर दी थी। अम्मार हुसैन के परिवार को सांत्वना देने के लिए पाक सेना ने 'सितारा-ए-जुर्रत' से सरफराज करके रावलपिंडी के चकलाला चौक का नाम 'अम्मार हुसैन चौक' रख दिया है। टाइगर हिल पर ही मारे गए कैप्टन 'करनल शेर खान' का शव भारतीय सेना ने पूरी अकीदत से पाकिस्तान को सौंपा था। 18 जुलाई 1999 को शेर खान की मय्यत जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो कराची के कोर कमांडर 'मुजफ्फर उस्मानी' ने शेर खान के ताबूत को खुद कंधा दिया। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर 'मोहिंद्र प्रताप सिंह बाजवा' की सिफारिश पर पाक ने शहीद करनल शेर खान को अपने आलातरीन सैन्य एजाज 'निशान-ए-हैदर' से नवाजा था। सैकड़ों पाक सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने के बावजूद पाक सेना कारगिल घुसपैठ में अपने किरदार को नकारती रही है। लेकिन नसीम जेहरा जैसे पाकिस्तान के कई सहाफियों व शाहिद अजीज जैसे पाक जरनैलों ने कारगिल साजिश में मुल्लविश पाक फौज को अपनी किताबों में तफसील से बेनकाब किया है।

कुछ अलग

फर्जी सर्टिफिकेट भंडार

क्षमा कीजिएगा, बुरा लगे तो! पर हर योग्य से अयोग्य जीव आज सरकारी क्षेत्र में जाने को हाथ पांव न होने के बाद भी दिनरात हाथ पांव मार रहा है। क्योंकि गधे से भी गधे का मानना है कि यह करियर मरने के बाद भी परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। यह करिअर हाथ पर टांग धरे खाने कमाने के असीम से असीम अवसर देता है। और जो पद जमकर खाने कमाने वाला मिल जाए तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में। सरकारी क्षेत्र में इन्हीं नौकरी पाने वाले अयोग्यों को खानापूर्ति के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के साथ कुछ अनावश्यक दस्तावेज सबमिट करने ही पड़ते हैं ताकि चयन में पारदर्शिता दिखती रहे। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर जीव के लिए अलग-अलग होता है। मसलन, जो कोई नेता जी के सपोर्टर का कैंडिडेट है तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग, जो नेता जी का कैंडिडेट है तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग और अगर जो कोई केवल और केवल कैंडिडेट है तो उसके लिए तो क्राइटेरिया बिल्कुल ही अलग। जब फर्जी को समाज में हर जगह जमकर मान्यता मिल रही है तो ऐसे में सरकारी नौकरी वैधानिक, सवैंधानिक फर्जी सर्टिफिकेटों से पाने के इच्छुकों को यह सूचना देते हुए हमें प्रसन्नता नहीं, हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हमने सरकारी नौकरियों में फर्जी सर्टिफिकेटों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हर राज्य में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अपना गुणवत्तापूर्ण प्रामाणिक फर्जी सर्टिफिकेट भंडार खोल दिया है जहां से वाजिब दामों में सर्वसाधारण को भी फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध हो सकेंगे ताकि आने वाले समय में असली सर्टिफिकेटों को दो हजार के नोटों को जनहित में चलन से बाहर किया जा सके। हमारे इस फर्जी सर्टिफिकेट भंडार से कम पैसे वाले भी सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह का अपनी जरूरत के हिसाब से फर्जी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। स्मरण रहे, हम फर्जी सर्टिफिकेट खरीदने वालों को लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। हे फर्जी सर्टिफिकेटों के जागरूक उपभोक्ताओ! समाज में आज कुछ भी असली नहीं, समाज में सब फर्जी है। अगर असली कुछ है भी तो उसे पूछता ही कौन है? यहां देशभक्ति से लेकर मातृभक्ति तक सब फर्जी है। यहां राइटर फर्जी। यहां फाइटर फर्जी है। यहां संबंध फर्जी है। संबंधों की सुगंध फर्जी है। यहां सद्कर्म फर्जी है। यहां धर्म फर्जी है। यहां नेता फर्जी है। यहां वोटर फर्जी है। यहां सपोर्टर फर्जी है। यहां पोर्टर फर्जी है। यहां ड्राइवर फर्जी है। यहां मोटर फर्जी है। यहां जन सेवा फर्जी है। यहां नंगों को कपड़े सिलने वाला दर्जी फर्जी है। सरकारी नौकरी पा रिटायरमेंट के बाद भी मजे करने वाले अयोग्यों के लिए हमारे प्रामाणिक भंडार में हर किस्म के असली को भी कदम कदम पर मात देने वाले फर्जी सर्टिफिकेट चौबीसों घंटे ऑनलाइन, ऑफलाइन हर समय उपलब्ध हैं। हम अपने असली को भी मात देने वाले फर्जी सर्टिफिकेटों को लेकर सौ नहीं, एक सौ एक प्रतिशत आश्वस्त हैं कि हमारे फर्जी फर्जी सर्टिफिकेटों को ये वे तो ये वे, भगवान भी चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे पास आईएएस से लेकर पीउन तक की सरकारी नौकरी पाने के लिए जिन जिन सर्टिफिकेटों की जरूरत पड़ती है, वे सब सहज उपलब्ध हैं। इन्हें उन्हीं हूबहू उन जैसे अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है जिन्हें उन्हें असल में किया जाना चाहिए। शहर के सौ सालों से मशहूर शर्मा मिष्ठान भंडार की मिठाइयां खाकर भले ही शहर के हर दूसरे बंदे को शूगर हो रही हो तो होती रहे, पर क्या मजाल जो किसी एक पर भी हमारे फर्जी प्रामाणिक सर्टिफिकेट भंडार से फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी नौकरी पाने वाले किसी कर्मचारी पर उसके मरने के बाद भी केस चले।

देश दुनीया से

भारत में तेजी से हो रहा है वित्तीय समावेशन

केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देश के गरीब वर्ग को दी जाने वाली सहायता/प्रोत्साहन राशि को भी इन खातों में आज सीधे ही जमा कर दिया जाता है, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिससे इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि इससे अंततः लीकेज कम हुए है और यह सुनिश्चित हुआ है कि योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक सीधे ही पहुंचे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के दूर दराज के इलाकों में निवासरत नागरिकों को बैंकिंग, बचत और जमा खाते, राशि हस्तांतरण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक एवं पेन्शन क्षेत्र के हितधारकों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित किया है। दरअसल, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतुलनीय प्रगति को दर्शाने के लिए अब अपने सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत विदेशी संस्थानों द्वारा विकसित किए गए सूचकांकों के आधार पर किए जाने वाले सर्वे में तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रभावशाली प्रगति की सही तस्वीर पेश नहीं की जा रही है। इन सूचकांकों के आधार पर किए गए कई सर्वे में तो आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे, एक सर्वे में भुखमरी के क्षेत्र में भारत की स्थिति को अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश से भी बदतर बताया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किए गए वित्तीय समावेशन सूचकांक के आधार पर मार्च 2024 के परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार, भारत में वित्तीय समावेशन मार्च 2017 में 43.4, मार्च 2021 में 53.9 एवं मार्च 2023 में 60.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 प्रतिशत हो गया है। यह सूचकांक भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई अतुलनीय एवं स्थिर प्रगति को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों (नागरिकों की वित्तीय संस्थानों पर बढ़ती पहुंच, वित्तीय उत्पादों का बढ़ता उपयोग एवं वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता) पर देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जानकारी को 0 से 100 तक के मान में बताता है। यदि मान कम है तो देश में वित्तीय समावेशन भी कम है और इसके विपरीत यदि मान अधिक है तो देश में वित्तीय समावेशन भी अधिक है। भारत में यह मान मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 प्रतिशत हो गया है। उक्त वर्णित तीन आयामों में कई पैरामीटर शामिल हैं, इनका मूल्यांकन 97 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इस कार्यप्रणाली के कारण ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन का एक व्यापक संकेतक बन गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी देश में वित्तीय समावेशन के बढ़ने का आश्य यह है कि उस देश के नागरिकों की उस देश के बैंकिंग संस्थानों तक पहुंच बढ़ रही है और यह उस देश की अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। वर्ष 2014 में भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में गरीब वर्ग के जमा खाते खोलकर उन्हें वित्तीय समावेशन का हिस्सा बना लिया गया था। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं एवं इन जमा खातों में लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देश के गरीब वर्ग को दी जाने वाली सहायता/प्रोत्साहन राशि को भी इन खातों में आज सीधे ही जमा कर दिया जाता है, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिससे इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि इससे अंततः लीकेज कम हुए है और यह सुनिश्चित हुआ है कि योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक सीधे ही पहुंचे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के दूर दराज के इलाकों में निवासरत नागरिकों को बैंकिंग, बचत और जमा खाते, राशि हस्तांतरण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जनधन योजना पूर्ण रूप से सफल रही है और भारत में वित्तीय समावेशन को अगले स्तर पर ले जाने में भी सहायक रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए जमा खातों को भारत की विशिष्ट पहचान प्रणाली (आधार कार्ड) से जोड़कर, केंद्र सरकार ने देश में वित्तीय लेन देन प्रणाली को सुव्यवस्थित कर लिया है एवं बैंकिंग व्यवहारों में धोखाधड़ी की सम्भावना को कम करने में भी सफलता अर्जित की है। आज भारत की प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना के रूप में पहिचान मिली है। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज भी वित्तीय समावेशन के मुख्य उपकरण के रूप में माना जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों के खाते विभिन्न बैंकों में उसी उत्साह से लगातार खोले जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी भारत के विभिन्न बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 3.3 करोड़ नए जमा खाते खोले गए हैं इससे इस योजना के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या बढ़कर 51.95 करोड़ हो गई है एवं इन जमा खातों में 234,997 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है।

आप का नजरीया

अब संघ वर्जित नहीं

अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के सदस्य बन सकेंगे। अभी तक इस पर पाबंदी थी। 30 नवंबर, 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी को एक ही श्रेणी में रखकर पाबंदी लगाई थी। यानी इतना कट्टरपंथी और सांप्रदायिक हिंसावादी करार दिया गया था। ऐसे ही ऑफिस मेमोरेंडम (एमओ) 1970 और 1980 में भी जारी किए गए थे। तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थीं। करीब 58 साल के बाद इन एमओ की समीक्षा की गई और आरएसएस का नाम हटा दिया गया। संघ पर से पाबंदी हटा दी गई। नतीजतन किसी भी स्तर का सरकारी कर्मचारी अब घोषित तौर पर संघ का सदस्य बन सकता है। सार्वजनिक रूप से संघ की शाखाओं में भी शामिल हो सकेंगे। संघ के समारोहों और अभियानों में भी शिरकत कर सकेंगे। संघ पर पाबंदी नहीं रही, लेकिन संघ की सोच और विचारधारा के सरकारी कर्मचारी छिप-छिप कर शाखाओं में तो जाते थे। ऐसा हमारा पुराना अनुभव रहा है। संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक राष्ट्रवादी, सामाजिक संगठन है, जिसके 5.85 लाख सदस्य बताए जाते हैं। देश भर में संघ की 60,000 से अधिक शाखाएं हररोज लगती हैं। संघ राष्ट्रवादी, हिंदूवादी है, लेकिन अतिवादी नहीं हो सकता। यह एहसास देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार पटेल को हुआ, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में आरएसएस पर पाबंदी थोप दी थी। 1948 में पाबंदी और 1949 में पश्चाताप...नतीजतन पाबंदी हटा ली गई। ऐसा ही एहसास तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को हुआ, जिन्होंने भारत-चीन युद्ध के बाद पहले गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी के राष्ट्रीय आयोजन के अवसर पर संघ को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया था, लिहाजा संघ कैसे बच सकता था? वह पाबंदी 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान हटाई गई। 1992 में अयोध्या विवाद की हिंसा के मद्देनजर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी संघ पर पाबंदी चस्पा की, लेकिन 4 जून, 1993 को उसे वापस भी ले लिया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगते रहे हैं और उसे अतिवादी, उग्रवादी भी समझा जाता रहा है, लेकिन उसका राष्ट्रवाद कइयों की समझ से परे है। संघ सनातनवादी सोच का भी है, लेकिन मुसलमान को भी एक ही डीएनए की प्रजाति मानता है, लिहाजा वह तिरस्कृत नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल सत्ता में रहने के बाद संघ की वर्जनाओं को समाप्त किया है, सरकारी कर्मचारियों के प्रवेश के रास्ते खोले हैं, लिहाजा इस निर्णय पर भी सवाल किए जा रहे हैं। संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। नाराज संघ को मनाने की कोशिश बताया जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने इस निर्णय को 'संविधान के खिलाफ' करार दिया है और सरकारी दफ्तरों, संस्थानों पर संघ के कब्जे की परोक्ष कोशिश माना है। आरएसएस का मानना है कि नया फैसला और पाबंदियों से मुक्ति भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही मजबूत करेगी। संघ की स्थापना 1925 में की गई थी, लिहाजा यह संघ का शताब्दी-वर्ष है। इतने लंबे दौर में संघ ने खुद को जिंदा और प्रासंगिक रखा है, यह संघ का अनुशासन और संगठन ही है।

देश की जनता ने मोदी पर विश्वास जताकर कांग्रेस को दिया करारा जवाब : भूपेंद्र चौधरी

जयपुर (हिंस)। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर से यूपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात कर मंत्रणा की। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेसी नेता तुष्टिकरण की नीति पर काम कर रहे है। कांग्रेस केवल झूठ की दुकान चला रही है और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेसी नेताओं ने जनता के बीच नेगेटिव एजेंडा सेट करने का काम किया है, लेकिन देश की जनता कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं के इस नेगेटिव एजेंडे को समझ गई है। देश की जनता ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। यूपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये भाजपा ही है जो आस्था और परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। भाजपा ने 500 सालों से लंबित जन जन के आस्था के केंद्र राम मंदिर का निर्माण करवाकर जन भावनाओं का सम्मान किया है। चौधरी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया।

नौकरियों में बीसीए को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के फॉमूले को स्पष्ट करे भाजपा : दुष्यंत चौटाला

गठबंधन सरकार में लागू हो चुके फैसलों को दोबारा लागू करने का वादा कैसे कर सकते है शाह : दुष्यंत

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में नौकरियों में बीसीए वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा पर भाजपा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घोषणा को कैसे पूरा करेगी? इसका जवाब दें, क्योंकि आज हरियाणा अपने निर्धारित आरक्षण कोटे के आंकड़े को छू चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा दोगली नीति अपनाते हुए हरियाणा में बीसीए को आरक्षण देने और राजस्थान में उनसे छीनने का काम कर रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नारनौल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीसीए वर्ग को ग्रुप डी की नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पर सरकार बताए कि इसका प्रावधान अलग से करेगी या बीसी का ही आरक्षण काटकर प्रावधान किया जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा आरक्षण के आंकड़े 49.9 प्रतिशत को छू चुका है और कानूनी तौर पर इससे ज्यादा आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीसीए को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा दर्शाती है कि किसी के आरक्षण में से कटौती होगी या फिर हरियाणा भी तमिलनाडु की तर्ज पर केंद्र सरकार से कानूनी संशोधन करवाया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि भाजपा आरक्षण को लेकर दोगली नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां अमित शाह हरियाणा में बीसीए वर्ग के आरक्षण के लिए इतनी बड़ी घोषणा करते है, वहीं इस घोषणा के मात्र 16 घंटे के बाद ही राजस्थान की भाजपा सरकार प्रमोशन में बीसीए वर्ग का आरक्षण हटा देती है। यानी भाजपा देश में बीसी वर्ग में बंटवारा कर रही है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक और बयान पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि शाह द्वारा हरियाणा में पंचायतों और निकायों में बीसीए वर्ग को आठ प्रतिशत आरक्षण देने का वादा करना भी उचित नहीं है क्योंकि यह दोनों निर्णय ढाई साल पहले पूर्व गठबंधन सरकार ने लागू कर दिए थे।

कांग्रेस व जजपा ने स्पीकर की कार्यशैली पर उठाए सवाल

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा विधानसभा में तीन विधायकों की सदस्यता को लेकर स्पीकर के यहां में चल रही लड़ाई अब और गहरा गई है। एक तरफ सरकार विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने जा रही है तो दूसरी तरफ जजपा और कांग्रेस ने स्पीकर पर अपने विधायकों की सदस्यता रद्द करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता व चीफ व्हीप ने विधानसभा स्पीकर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। शुक्रवार को जजपा नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल स्पीकर से मिला। इस मुलाकात के दौरान दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही पार्टी के दो विधायकों बरवाला से जोगीराम सिहाग और नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। दोनों ही विधायकों के खिलाफ जजपा के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने शिकायत की हुई है। स्पीकर ने लंबे समय के बाद दोनों विधायकों को नोटिस जारी करके इस मामले में सुनवाई करने का फैसला लिया है। दुष्यंत ने स्पीकर से मुलाकात करके उनसे आग्रह किया कि इस मामले में सप्ताहभर में सुनवाई करके फैसला किया जाए। दोनों विधायकों पर दल-बदल कानून के तहत आरोप लगे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ने न केवल भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया बल्कि भाजपा के प्लेटफार्म पर भी शामिल हुए। रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग इसके बाद भी खुलकर राज्य की मौजूदा नायब सिंह सैनी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। दुष्यंत का कहना है कि पूर्व स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने उस समय इनेलो विधायकों की सदस्यता रद्द करने में जरा भी देरी नहीं की थी। अब चूंकि जजपा के विधायक भाजपा की बोली बोल रहे हैं, इसलिए स्पीकर फैसला करने में देरी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, तोशाम विधायक किरण चौधरी ने 18 जून को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

अखिलेश यादव सपा को समाप्त होने से बचाएं : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से बचाएं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने

से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहरायेगी, कमल खिला है खिलेगा, खिलता रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और इनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रही है। कांग्रेस के मोहरा बने अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर शहीद वीर सैनिक किए गए याद

बिजनौर (हिंस)। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने व रजत जयंती के अवसर पर काकरान वाटिका में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर वीर जवानों एवं उनके बलिदान को याद कर सैनिकों एवं उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने विजय दिवस के 25 वें वार्षिक समारोह के आयोजन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिले के विद्यालयों में जाकर बच्चों को देश की महान विभूतियों एवं देश के वीरों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें, जिससे युवा फीढ़ी में देश प्रेम की भावना जागृत हो। उन्होंने कहा कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहां राष्ट्रहित व राष्ट्रप्रेम सर्वोपरि है और हम सभी लोग एकजुट होकर

इस देश की एकता व अखण्डता को बनाये रखने के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। देश के वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान व उनके परिवार का योगदान को शब्दों मे नहीं बताया जा सकता। कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी ने सैन्य अधिकारियों, शहीद सैनिकों की वीर नारियों व आश्रितों को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेट कर सम्मानित किया। इस मौके पर देश भक्ति, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बच्चों द्वारा दहेज दानव नाटय की सुंदर प्रस्तुति दी गई और अन्य देश भक्ति संगीत पर प्रस्तुतियों भी प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पारितोषिक वितरण कर सम्मानित भी किया।

रोडवेज कर्मचारियों ने फूंका विधायक यूनुस खान का पुतला

जोधपुर (हिंस)। रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को पूर्व परिवहन मंत्री एवं वर्तमान निर्दलीय विधायक यूनुस खान का पुतला फूंका। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि यूनुस खान ने विधानसभा में रोडवेज निगम के खिलाफ गलत बयान दिए हैं जिससे प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश है। इससे पहले रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड में विधायक यूनुस खान के पुतले की शवयात्रा निकाली। इसके बाद पुतला फूंका गया। रोडवेज कर्मचारियों ने यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि विधायक एवं पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान छह साल पहले जब वसुंधरा सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने वसुंधरा के साथ मिलकर एक साजिश के तहत राजस्थान रोडवेज को बंद करने के लिए लोक परिवहन को परमिट जारी किए थे।

बिहार विधानसभा में स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को दी चेतावनी, रिपोर्टर टैबल पर आए तो होगी कार्रवाई

पटना (हिंस)। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को दोनों सदनों (विधानसभा-विधानपरिषद) में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा में विपक्षी सदस्य का व्यवहार इतना उग्र था कि अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को गुस्सा आ गया। उन्होंने वेल में आ रहे सदस्यों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि कोई भी सदस्य रिपोर्टर टैबल तक पहुंचा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल, कल विपक्ष के वेल में किए गए उग्र प्रदर्शन से एक कर्मचारी घायल हो गया था। इसके बाद शुक्रवार को सदन में जैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया वैसे ही अध्यक्ष ने भी तेवर सख्त कर लिए। अध्यक्ष के कड़े तेवर को देखकर विपक्षी दल के सदस्य भी वेल के बाहर ही नारेबाजी करते दिखे। बिहार विधानसभा की सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर महागठबंधन के विधायक बैनर-पोस्टर लेकर वेल में जाकर प्रदर्शन करने लगे। विधायकों का कहना था कि विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। महागठबंधन विधायक वेल में खड़े होकर नारे लगा रहे थे, जिसेक बाद स्पीकर बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि रिपोर्टर टैबल को कुछ भी करने की कोशिश किए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सदन की कार्यवाही हंगामे के बीच चलती रही और उसके बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। महागठबंधन विधायकों से स्पीकर अपनी-अपनी सीटों पर जाने के लिए कह रहे थे लेकिन महागठबंधन विधायक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इस बीच वाम दल विधायक सत्यदेव राम स्पीकर से कहा कि आप हम महागठबंधन विधायकों को मौका नहीं देते। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। हम लोगों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। इस पर स्पीकर ने कहा कि प्रश्नोत्तर के बाद आप लोगों को समय देंगे। विधानसभा को हाईजैक करने की कोशिश मत करिए। नियम कानून से सदन चलेगा। इससे पहले राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार को उसका हक हम लोग दिलवाकर रहेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार को धोखा दिया है। बिहार का विकास तभी होगा जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ऐसे कैसे केंद्र सरकार ने संसद में कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। इस मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश को इस मुद्दे पर साथ आना है तो आएं।

बारिश के बीच कचरा नहीं उठने से बढ़ने लगा बीमारियों का खतरा

जयपुर (हिंस)। बारिश के बीच सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से मौसमी बीमारियों के बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। हड़ताल के चलते कचरा नहीं उठने से जगह-जगह कचरें के ढेर नजर आने लगे है। कचरे के ढेर के पास मवेशियों के मंडराने के साथ मक्खी-मच्छर पनपने लगे है जो कि मौसमी बीमारियों को बड़ा सकते है। शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने जुलूस निकाला। हैरिटेज मुख्यालय नगर निगम जलेबी चौक में वार्डों से जुलूस के रूप में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हैरिटेज से हवामहल बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ तक सफाई कर्मचारी एवं सफाई संगठनों के पदाधिकारियों ने न्याय रैली निकाली। सफाई कर्मचारियों हाथों में झाड़ू, तखतियां, बैनर लेकर मांगो को पूरा करने के लिए नारों के साथ जुलूस

निकाला। रैली के दौरान छोटी चौपड़ पर मुख्यमंत्री के नाम 2 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। इसमें सफाई कर्मचारी भर्ती मस्ट्रोल पर की जाए एवं 2012 एवं 2018 के कोर्ट केस के प्रकरणों को नियुक्ति दी जाए। छोटी चौपड़ से न्याय रैली वापस त्रिपोलिया बाजार होते हुए हैरिटेज मुख्यालय में सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को वाल्मीकि समाज के सुरेश कल्याणी, कैलाश किशन लोहरा, किशन लाल जैदिया, सत्यनारायण भूमलिया, अमित कल्याणा, उमेश वाल्मीकि, सुरेश बिवाल, अशोक भाया, झूमर चन्द कोठयारी, मनोज चौहान, कमल लखन, मुकेश बिवाल और सुरेश डाबोडिया ने सम्बोधित किया। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले समय में सफाई काम में जुटे कर्मचारियों को भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते निगम प्रशासन ने आमजन को गदंगी से बचाने के लिए कमर कस ली है।

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY :: NAGAON (ASSAM)
ADVERTISEMENT

In **partial modification** to our earlier advertisement conveyed vide **memo no. DLSA- N/ 2024/1641-49 dated 15.06.2024,** fresh applications are invited in Standard Form, from Intending candidates for filling up the following vacant post on contractual basis under the LADCS Modified Scheme 2022, in the establishment of District Legal Services Authority, Nagaon. The candidates who have already applied for the above mentioned posts need not make fresh applications.

Sl. No.	Name of the post	No. of Vacant Post	Pay	Category	Age Limit	Educational Qualification
01.	Receptionist -cum- Data Entry Operator (on contractual basis)	1 nos.	Rs. 18,000/- (Fix pay per month)	Unreserved	18 years to 40 years as on 01.01.2024 (Relaxation as per Govt. rules)	Graduation in any stream from a recognized University along with a 06 (six) months diploma/ certificate course in computers with proficiency in MS Office, internet and email. Candidate should also possess good verbal and written communication skills, and ability to work in telecommunication systems.
02.	Office Assistant (on contractual basis)	3 nos.	Rs. 18,000/- (Fix pay per month)	Unreserved	-Do-	Graduation in any stream from a recognized University along with a 06 (six) months diploma/ certificate course in computers with proficiency in MS Office, internet and email. Candidate should have the ability to take dictation and prepare files for presentation in the courts.
03.	Peon (on contractual basis)	3 nos.	Rs. 12,500/- (Fix pay per month)	Unreserved	-Do-	Class VIII pass. Candidates who have passed HSSLC or above shall be ineligible to apply.

General terms and conditions :

1. The candidate must be an Indian citizen as defined in Article 5 to 8 of the Constitution of India.
2. The appointment shall be purely temporary and on contractual basis and does not entitle the person for being regularized in Govt. Service.
3. After expiry of contract period of 01 (one) year, the contractual agreement will automatically stand terminated.
4. The service may be extended after appropriate break in service, subject to the approval of the Hon'ble Chairman, District Legal Services Authority, Nagaon.
5. The candidates for Receptionist-cum-data Entry Operator and Office Assistant shall also possess good typing speed with proper drafting qualities, file maintenance and processing knowledge.
6. If any candidate is found to have suppressed his educational qualification or given any wrong information at the time of applying for the post, his candidature shall be laible to be rejected, summarily without assigning any reason.
7. The last date of receipt of application is 10 (ten) days from date of publication of the advertisement. The office shall not be liable for any postal delay.
8. Duly filled applications on Standard Form of application (Assam Gazette Part IX) along with self attested photocopies of all the relevant testimonials and 02 (two) copies of recent Passport size photographs should be addressed to **The Secretary, District Legal Services Authority, Nagaon, Room No. 63, 4th Floor Judicial Court Building, Nagaon, Assam, Pin-782001.**
9. Contact numbers and email id (if any) must be provided in the application. If mobile numbers are not provided the candidature will be rejected.
10. The applicants have to deposit their application in a sealed envelope in the **"DROP BOX"** provided for the purpose in front of the premises of the office of the **Secretary, District Legal Services Authority, Nagaon, Room No. 63, 4th Floor Judicial Court Building, Nagaon, Assam, Pin-782001.** Applicants may also send their applications through post at the same address. The office shall not be liable for any postal delay.
11. The applicant must mention at the top of the envelope containing the application **"APPLICATION FOR THE POST OF OFFICE RECEPTIONIST – CUM – DATA ENTRY OPERATOR"** for candidates intending to apply for the Post of Receptionist-cum-Data Entry Operator, **"APPLICATION FOR THE POST OF OFFICE ASSISTANT"** for Candidates intending to apply for the post of Office Assistant and **"APPLICATION FOR THE POST OF PEON"** for candidates intending to apply for the post of Peon.
12. The eligible candidates for all the posts shall have to appear for viva-voca. The candidates short listed in the viva-voca for the post of Receptionist -cum- data Entry Operator and Office Assistant shall also appear for skill test (Computer).
13. The list of eligible candidates will be uploaded in the official website of Nagaon Judiciary *(nagaon.dcourts.gov.in)* with the date of interview and skill test and intimated on their respective mobile phones.
14. No separate call letter will be issued from this office.
15. All other information relating to recruitment process (including final results) will be published in the official website of Nagaon District Judiciary.
16. All the applicants are advised to visit the official website frequently.
17. Canvassing directly or indirectly shall disqualify a candidate.
18. No TA/DA will be admissible to the candidates.

Sd/-
District & Sessions Judge -cum-Chairman,
District Legal Services Authority,
Nagaon, Assam.

-- Janasanyog /D/3037/24/27-Jul-24

यूनिवर्सल म्यूजिक स्टॉक को लगा बड़ा झटका स्ट्रीमिंग और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में आई गिरावट

नई दिल्ली ।
यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी के शेयर में 24 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने खुलाया किया कि उनके स्ट्रीमिंग और सब्सक्रिप्शन सेवाओं से रेवेन्यू उम्मीद से काफी कम आया है। यह गिरावट ग्रुप के बाजार मूल्य में 16 बिलियन डॉलर (भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 1600 करोड़) की गिरावट को दर्शाती है, जिसमें टेलर स्विफ्ट, ड्रेक, एडेल और बिली इलिश जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

क्या है इस गिरावट का कारण - इस गिरावट का कारण इसकी स्ट्रीमिंग और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के औसत परिणाम हैं। कंपनी की दूसरी तिमाही की सदस्यता आय में विदेशी मुद्रा (एफएक्स) को छोड़कर साल-दर-साल 6.9 फीसदी की वृद्धि हुई। यह पहली तिमाही में 12.5 प्रतिशत से कम है। तीसरी तिमाही में स्ट्रीमिंग राजस्व में 3.9 फीसदी की कमी देखने को मिली, जो दर्ज 10.3 प्रतिशत की वृद्धि से काफी रिवर्स है। इस कमी के लिए मुख्य विज्ञापन-आधारित प्लेटफॉर्म भागीदारों में वृद्धि में मंदी और सौदे के नवीनीकरण के समय से संबंधित कुछ प्लेटफॉर्म पर कमी को जिम्मेदार ठहराया गया।

मेटा के साथ समाप्ता की साझेदारी - मई में यूएमजी ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी थी, जो कि फेसबुक के लिए प्रीमियम संगीत वीडियो का लाइसेंस दे रहा था। यूएमजी को नए लाइसेंसिंग समझौते को लेकर टिक टॉक के साथ हाई-प्रोफाइल लड़ाई के दौरान एक महीने के रेवेन्यू का भी नुकसान हुआ। यूएमजी के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी बॉयड मुइर ने कहा कि सब्सक्रिप्शन वृद्धि में साल-दर-साल गिरावट आंशिक रूप से उसके भागीदारों द्वारा मूल्य वृद्धि के समय के कारण थी।

यूएमजी के साझेदारों में शामिल हैं ये कंपनियां - यूएमजी के साझेदारों में स्पॉटिफाई (एसपीओटी), अमेजन म्यूजिक (एएमजेडएन) और एप्पल म्यूजिक (एएपीएल) जैसी ऑडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। मुइर ने कहा, इस तिमाही में हमारे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक कुछ प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर ग्रोथ में मंदी है।

न्यूज ब्रीफ

इंडिगो पर अमेरिकी कस्टम विभाग ने लगाया जुर्माना, विमान में देरी से इस्तांबुल में घंटों फंसे यात्री

नई दिल्ली । अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने आव्रजन उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में देरी के लिए इंडिगो एयरलाइंस पर 5,832.60 डॉलर (488333.27 रुपये) का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने नियत तारीख (गैर-इंटरलाइनेबल टैक्स) के बाद आव्रजन उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के लिए जुर्माना लगाया है। कंपनी जुर्माने में छूट हासिल करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने एक नियामकीय फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा है कि इसके वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर बीएसई पर 1.22 फीसदी की तेजी के साथ 4,430.50 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। इंडिगो को अमेरिकी प्राधिकरण से जुर्माने के बारे में 24 जुलाई को सूचना मिली थी इस्तांबुल में फंसे इंडिगो के 200 यात्री एक अलग घटनाक्रम में, एयरलाइन को 200 यात्रियों को इस्तांबुल हवाई अड्डे पर इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने इसकी ऑनलाइन आलोचना की। दरअसल, दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ान को 12 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। विमान में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को देर तक इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने उड़ान में देरी की आलोचना की देरी से चल रही उड़ान 6ई 12 के एक यात्री हृदय मदान ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा, इंडिगो एयरलाइंस की बिल्कुल दयनीय सेवा। मैं और मेरी पत्नी मिलान से इस्तांबुल इंडिगो-तुर्की एयरलाइंस के साथकोडशेयर बुकिंग के जरिए लौट रहे हैं। 6ई12 से आगे दिल्ली के लिए हमें जाना है। हम इस्तांबुल में दोपहर 3 बजे उतरे और अब हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट में देरी हो गई है। एक अन्य यात्री गोविंद कनकन ने लिखा, इस्तांबुल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए इस्तांबुल हवाई अड्डे पर दयनीय स्थिति। तुर्की इंडिगो 6ई-12 की उड़ान में अब छह घंटे से अधिक की देरी हुई है और ऑपरेटर लापरवाह है। हवाई अड्डे पर यात्रियों को दिया जाने वाला भोजन बासी है। इंडिगो ने बयान जारी कर खेद जताया इंडिगो ने एक बयान जारी कर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। बयान में कहा गया है, यात्रियों को देरी के बारे में सूचित किया गया, जलपान परोसा गया और हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए आवश्यक व्यवस्था तुरंत की गई।

जल्द लांच हो सकता है शाओमी 14 टी प्रो फोन, फोन के कुछ फीचर्स हो गए पहले ही लीक

नई दिल्ली । चाइनीज कंपनी शाओमी जल्द ही शाओमी 14 टी प्रो लांच कर सकती है। हालांकि कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन फोन के कुछ फीचर्स पहले ही लीक हो गए हैं। एक नए लीक से फोन कैमरे के बारे में पता चला है। एक टिपस्टर के मुताबिक शाओमी 14 टी प्रो में 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फोन का टेलीफोटो कैमरा लेइका के साथ पेश किया सकता है। इसके अलावा, ऐसा कहा जा रहा है कि शाओमी 14 टी प्रो में रेडमी के 70 अल्ट्रा की तरह स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं, जिसे हो सकता है अगले महीने लॉन्च किया जाए।

एनबीए ने वार्नर ब्रदर्स के साथ तोड़ी डील, डिस्कवरी और एचबीओ मैक्स को भी लगा झटका

नई दिल्ली । वार्नर ब्रदर्स एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। एनबीए द्वारा तीन बड़े राइट्स डील की घोषणा के बाद वार्नर ब्रदर्स के शेयर काफी नीचे आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एनबीए ने वार्नर ब्रदर्स के साथ डील ब्रेक कर लिया है जिसके वजह से वह पेशेवर बास्केटबॉल से बाहर हो गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। एनबीए ने तोड़ी डील वार्नर ब्रदर्स के शेयर बाजार के खुलने के बाद लगभग आठ प्रतिशत गिरे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी वजह एनबीए द्वारा वार्नर ब्रदर्स के प्रतिद्वंदी कंपनी के साथ डील कर लेना है। एनबीए के इस सौदे की वजह से वार्नर ब्रदर्स को काफी नुकसान उठाना पर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब वार्नर ब्रदर्स के डिस्कवरी को व्यावसायिक बास्केटबॉल से बाहर रख दिया गया है। वार्नर ब्रदर्स के शेयर हुए सस्ते मैक्केरी इक्विटी रिसर्च के टिम नोलन के मुताबिक वार्नर ब्रदर्स को भविष्य में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि, वार्नर ब्रदर्स के शेयर निकट भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वार्नर ब्रदर्स के शेयर पहले से ही सस्ते हैं और अब उनका मूल्य भी काफी कम हो गया है। इसमें निवेश करना घाटे का सौदा हो सकता है। वार्नर ब्रदर्स करेंगे करवाई एनबीए ने वार्नर ब्रदर्स की प्रतिद्वंदी कंपनी के साथ सौदा कर लिया है।

सात समंदर पार इंग्लैंड-अमेरिका

चला काला नमक चावल

लखनऊ।
भगवान बुद्ध के महाप्रसाद कहा जाने वाला काला नमक चावल विदेशों की सैर पर निकलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे ओडीओपी घोषित करने के बाद इसके क्रेज में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले तीन साल में तीन गुने से अधिक का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट लक्ष्य हासिल करने वाले काला नमक चावल को लगभग सात दशक बाद इंग्लैंड और पहली बार अमेरिका भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

इसके पहले नेपाल, सिंगापुर, जर्मनी, दुबई आदि देशों को भी काला नमक चावल का निर्यात किया जा चुका है। सरकार की तैयारी के मुताबिक इस वर्ष पहली बार इंग्लैंड और अमेरिका को 5-5 क्विंटल काला नमक चावल का निर्यात होगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इंग्लैंड तो काला नमक चावल के स्वाद और सुगंध का मुरीद रह चुका है।

बात करीब सात दशक पुरानी है। तब, गुलाम भारत में देश भर में अंग्रेजों के बड़े-बड़े फॉर्म हाउस हुआ करते थे। ये इतने बड़े होते थे कि इनके नाम से उस क्षेत्र की पहचान जुड़ जाती थी। मसलन बर्डघाट, कैंपियरगंज आदि। सिद्धार्थनगर भी इसका अपवाद नहीं रहा। उस समय सिद्धार्थनगर में अंग्रेजों के फॉर्म हाउसेज में काला नमक धान की बड़े पैमाने पर खेती होती थी। अंग्रेज, काला नमक चावल के स्वाद और सुगंध से वाकिफ थे। इन खूबियों के कारण इंग्लैंड में काला नमक चावल के दाम भी अच्छे मिलते थे। तब जहाज के जहाज चावल इंग्लैंड भेजे जाते थे।

लगभग सात दशक पहले जमींदारी उन्मूलन के बाद यह सिलसिला क्रमश: कम होता गया और आजादी मिलने के बाद खत्म ही हो गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जबसे काला नमक धान को सिद्धार्थनगर का एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) घोषित किया है, तबसे देश और दुनिया में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। स्वाद, सुगंध में बेमिसाल और पौष्टिकता में परंपरागत चावलों से बेहतर काला नमक धान के चावल के क्रेज में अभी बढ़ोत्तरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

राज्यसभा में 17 दिसंबर 2021 को दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2019/2020 में इसका निर्यात 2 फीसद था। अगले साल यह बढ़कर 4 फीसद हो गया। 2021/2022 में यह 7 फीसद रहा।

काला नमक धान को केंद्र में रखकर पिछले दो दशक से काम कर रही गोरखपुर की संस्था पीआरडीएफ (पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन) के चेयरमैन पदमश्री डॉ. आरसी चौधरी के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी संस्था ने सिंगापुर को 55 टन और नेपाल को 10 टन काला नमक चावल का निर्यात किया। इन दोनों देशों से अब भी लगातार मांग आ रही है। कुछ मात्रा में दुबई और जर्मनी को भी इसका निर्यात हुआ है। पीआरडीएफ के अलावा भी कई संस्थाएं काला नमक चावल के निर्यात में लगी हैं।

डॉ. चौधरी के अनुसार निर्यात का प्लेटफार्म बन चुका है। आने वाले समय में यह और बढ़ेगा। दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक चावल, जिसमें वीटा कैरोटिन के रूप में विटामिन ए उपलब्ध है। अन्य चावलों की तुलना में इसमें प्रोटीन और जिंक की मात्रा अधिक है। जिंक, दिमाग और प्रोटीन हर उम्र में शरीर के विकास के लिए जरूरी है। ग्लाईसेमिक इंडेक्स कम (49 से 52 प्रतिशत) होने से इसे शुगर के रोगियों के लिए भी मुफीद माना जाता है।

भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स का अधिग्रहण करेगी मैनकाइंड फार्मा 13,630 करोड़ में फाइनल हुई डील

नई दिल्ली ।
मैनकाइंड फार्मा और भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स को लेकर चल रही बातचीत आखिरकार फाइनल हो गई है। मैनकाइंड फार्मा एडवेंट इंटरनेशनल से भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स का पूर्ण अधिग्रहण करेगी। इसके लिए 13, 630 करोड़ रुपये में डील फाइनल हुई है।

कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर बताया कि मैनकाइंड फार्मा 13,630 करोड़ रुपये में भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने लगभग 13,630 करोड़ रुपये में भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स (बीएसवी) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के समझौते को अंतिम रूप दिया है। यह रणनीतिक कदम दवा निर्माता के लिए अहम माना जा रहा है। इससे उसे भारतीय महिला स्वास्थ्य और प्रजनन दवा बाजार में अग्रणी बनकर उभरने में मदद मिलेगी।

मनीकंट्रोल ने रिपोर्ट दी थी कि मैनकाइंड फार्मा इक्विटी-एडीआईए कंसोर्टियम से आगे निकल गई है और मेगा डील के लिए अग्रणी धावक के रूप में उभरी है। मनीकंट्रोल क्रमश: 2 और 20 दिसंबर को भारत सीरम्स की बिक्री योजनाओं और सेल-साइड सलाहकारों की नियुक्ति की रिपोर्ट करने वाला पहला व्यक्ति था।

डील फाइनल होने के बाद, मैनकाइंड फार्मा के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव जुनेजा ने कहा, बीएसवी का अधिग्रहण मानव जाति की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है, जो हमें भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षेत्र में बाजार के अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। हमारा मानना है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत विकास दृश्यता के साथ-साथ संरचनात्मक टेलविंड के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अवसर हैं। वहीं, बीएसवी के सीईओ और प्रबंध निदेशक संजीव नवांगुल ने कहा, यह अधिग्रहण अत्याधुनिक उत्पाद लाने और भारत के साथ दुनियाभर में लाखों मरीजों तक हमारी पहुंच बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। हमें उन कुछ भारतीय कंपनियों में से एक होने पर गर्व है, जिनके पास अपनी तरह के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जटिल उपचार हैं, जिन्होंने मरीजों को बेहतर परिणाम दिए हैं।

6 साल में पैदा हुई 16 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां, मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए लाखों अवसर

नई दिल्ली ।
पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। इसको लेकर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में कहा कि पिछले छह वित्त वर्षों में 16.83 करोड़ नई नौकरियां निकली हैं। वह कहती हैं कि जहां साल 2017-18 में रोजगार की संख्या 47.5 करोड़ थी, वो मार्च 2024 तक 64.33 करोड़ हो गई। शोभा करंदलाजे ने बताया कि यह लिखित जानकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डेटाबेस जारी किया था। इस डेटा के अनुसार पिछले 6 कारोबारी सालों में नए रोजगार की संख्या 64.33 करोड़ हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैदा हुई सबसे ज्यादा नौकरी श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं) में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देखने को मिले। साल 2017-18 से साल 2022-23 तक इस सेक्टर में रोजगार के अवसर में 85 लाख की तेजी देखने को मिला है। बाल श्रम को लेकर शोभा करंदलाजे ने कहा कि बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा

कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, बुनियादी सेवाओं की पहुंच में कमी आने की वजह से बाल श्रम पर रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि, सरकार इस पर रोक लगाने के लिए विधायी कार्रवाई, पुनर्वास रणनीति, मुफ्त शिक्षा का अधिकार दे रही है। इसके अलावा सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।

बाल श्रम को रोकने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आदर्श राज्य कार्य योजना किया है। इसमें राज्य बाल श्रम के उन्मूलन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्य बिंदुओं को सूचीबद्ध किया है।

आईटी राज्य मंत्री ने कहा-घरेलू मैन्युफैक्चरिंग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार; 8,282 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली ।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया, 8,282 करोड़ रुपये के निवेश में ग्रीनफील्ड कंपनियों (पैरेंट कंपनी की ओर से दूसरे देश में खोली गईअनुषंगी इकाई) की हिस्सेदारी 3,136 करोड़ रुपये रही। ब्राउनफील्ड कंपनियों (पहले से मौजूद सुविधाओं या अन्य संसाधनों पर निर्माण करने या उन्हें पट्टे पर लेने वाली इकाई)ने पीएलआई योजना के तहत 5,146 करोड़ का निवेश योगदान किया है। मंत्री ने बताया, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत बनाने को एक अप्रैल, 2020 को पीएलआई योजना शुरू गई थी। अब तक 32 कंपनियों को 11,324 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता के साथ मंजूरी दी गई है। सरकार ने पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों के चयन के बाद उत्पादन या निवेश

मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, कोविड-19 महामारी से प्रभावित कंपनियों को राहत देने के लिए पीएलआई योजना की अवधि को एक साल के लिए बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया है। पहले यह अवधि 2024-25 थी। कंपनियां उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2025-26 तक कोई भी पांच साल की अवधि चुन सकती हैं। आईटी हार्डवेयर: मिली 27 कंपनियों को मंजूरी राज्य मंत्री ने बताया कि आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना के तहत 27 कंपनियों को स्वीकृति दी गई है। इन्होंने 30 जून, 2024 तक कुल 464.66 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इनमें 6 ग्रीनफील्ड और 21 ब्राउनफील्ड कंपनियां हैं, जिन्होंने क्रमश: 78.57 करोड़ व 386.09 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। मार्च, 2021 में अधिसूचित पीएलआई योजना के तहत 14 आईटी हार्डवेयर कंपनियों को 2,517 करोड़ के निवेश और 1,60,751 करोड़ की उत्पादन प्रतिबद्धता के साथ स्वीकृति दी गई है। मई, 2023 में अधिसूचित पीएलआई 2.0 के तहत 27 कंपनियों को 2,955 करोड़ रुपये के निवेश और 3,51,647 करोड़ रुपये की उत्पादन प्रतिबद्धता के साथ मंजूरी दी गई है। सरकार ने 2024-25 के बजट में विभिन्न क्षेत्र में पीएलआई योजना के लिए12,493.02 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

उपभोक्ताओं को राहत, जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए करना होगा कम खर्च; अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

नई दिल्ली ।
लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के आम बजट में कई आयातित उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क में कटौती की है। इसका मकसद लग्जरी और जरूरी आयातित उत्पादों को अधिक सस्ता करना है। इस कदम से न सिर्फ मांग-खपत बढ़ेगी बल्कि अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। सोना और चांदी पर लगने वाले सीमा शुल्क को 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी किया गया है। इससे सोना और चांदी खरीदना सस्ता हो जाएगा। अभी 22 कैरेट सोने के आभूषण खरीदने पर 68,500 रुपये चुकाने पड़ते हैं। इसमें 15 फीसदी यानी 10,275 रुपये सीमा शुल्क जुड़ा रहता है। अब यही आभूषण खरीदने के लिए आपको 6 फीसदी की दर से सिर्फ 4,110 रुपये सीमा शुल्क देना पड़ेगा। इस तरह, करीब 6,165 रुपये बचेंगे। इसी प्रकार,

एक किलोग्राम चांदी खरीदने पर भारी बचत होगी। प्लैटिनम : प्लैटिनम पर सीमा शुल्क को 15.4 फीसदी से घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया गया है। इस कटौती के बाद 2.46 लाख रुपये के डीबीयर्स प्लैटिनम बैंक की 19,000 रुपये घट जाएगी। यानी इस बैंड के लिए आपको सिर्फ 2.27 लाख रुपये खर्च करने होंगे। मोबाइल फोन : मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 20 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया है।

इस कटौती के बाद जिस मोबाइल फोन को खरीदने के लिए पहले 60,000 रुपये (12,000 रुपये सीमा शुल्क) खर्च करने पड़ते थे, उसके लिए अब सिर्फ 57,000 रुपये (9,000 रुपये सीमा शुल्क) खर्च करने होंगे। इस तरह, सीमा शुल्क के मोर्चे पर कुल 3,000 रुपये की बचत हुई। मोबाइल फोन की तरह चार्जर पर सीमा शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की गई है। अब आपको 20 फीसदी की जगह 15 फीसदी ही सीमा शुल्क देना होगा। जिस आईफोन चार्जर के लिए आप पहले 7,500 रुपये खर्च करते थे, इस कटौती के बाद यह सिर्फ 7,162 रुपये में मिल जाएगा। कैंसर की दवाइयां : कैंसर की तीन दवाइयों पर सीमा शुल्क हटाकर इससे पीड़ित लोगों को बजट में बड़ी राहत दी गई है। इससे फेंफड़े के कैंसर की जो दवाई पहले 2.04 लाख रुपये की आती थी, वह अब करीब 19,000 रुपये सस्ती हो जाएगी। नेचुरल बालू : अगर आप घर बनाना चाहते हैं और उसमें आयातित नेचुरल बालू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब इसके लिए कम खर्च करना पड़ेगा।

भारत का आईफोन निर्यात अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली। भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। इसी का असर है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल द्वारा देश से किया जाने वाला निर्यात अप्रैल-जून में बढ़कर 3.8 अरब डॉलर हो गया है ज्ञात दें, सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम लाई गई है। इससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिला है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में एप्पल का निर्यात अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह वैश्विक कंपनियों द्वारा चीन+1 की रणनीति अपनाना है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी की ओर से वित्त वर्ष 24 में 8 अरब डॉलर की बिक्री भारत में की गई थी। इसमें सालाना आधार पर 33 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली थी। कंपनी की बिक्री बढ़ने की वजह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में प्रीमियम फोन के चलन में बढ़ोतरी होना है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि आईफोन की शिपमेंट में इस वर्ष 20 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। एप्पल एक काफी मजबूत ब्रांड है और देश में अपना वितरण नेटवर्क भी मजबूत कर रहा है, जिससे इसे और तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। सरकार की ओर से बजट 2024-25 में मोबाइल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर आधार सीमा शुल्क (बीसीडी) 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले छह वर्षों में मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं, निर्यात 100 प्रतिशत बढ़ा है। भारत में मोबाइल फोन के आयात में भारी कमी देखने को मिली है। मौजूदा समय में भारत में बिकने वाली 99 प्रतिशत मोबाइल घरेलू स्तर पर ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं।

भारत की झोली में पदक डालने को मेरठ की तीन बेटियां तैयार, पारुल बनाएंगी ये रिकॉर्ड

मेरठ।

पेरिस ओलंपिक खेल शुरू हो चुके हैं। भारत से भी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ियों का दल पेरिस पहुंच चुका है। मेरठ से भी तीन महिला खिलाड़ी भाला फेंक में अन्नू रानी, पैदल चाल और मिक्स रिले वॉक इवेंट में प्रियंका गोस्वामी और 5000 मीटर दौड़ व 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी प्रतिभाग कर रही हैं।

खिलाड़ी पेरिस पहुंच चुके हैं। ऐसे में खेल शुरू होने से पहले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ी छाए हुए हैं। खिलाड़ियों को सुपर हीरो के किरदार में पेश किया जा रहा है। मेरठ के इकलौता गांव की पारुल चौधरी को सोशल मीडिया पर सुपर वुमन बताकर उनका पोस्टर तैयार कर शेयर किया जा रहा है। खुद खिलाड़ियों ने भी अपने सोशल मीडिया एकाउंट में इन पोस्टर को शेयर किया है।

इनमें भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा सुपर मैन के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। अन्य खिलाड़ी भी किसी न किसी सुपर हीरो के रूप में दिखाई दे रहे हैं। खुद खिलाड़ियों ने अपने पोस्टर को अपने सोशल मीडिया एकाउंटस से शेयर किया है। खिलाड़ी पेरिस पहुंचने के बाद अपनी फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। यहां मेरठ के खिलाड़ियों के परिजनों को भी सभी खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। 27 जुलाई को भारत और न्यूजीलैंड के बीच हॉकी मैच होना है जो कि काफी रोमांचक रहेगा।

इसके बाद एक अगस्त से एथलेटिक्स इवेंट शुरू होंगे, जिसमें मेरठ के खिलाड़ी भी नजर आएंगे। पैदल चाल में एक अगस्त को हिस्सा लेंगी प्रियंका गोस्वामी पेरिस ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स इवेंट एक अगस्त से शुरू होंगे। मेरठ से प्रतिभाग कर रहीं एथलीट प्रियंका गोस्वामी एक अगस्त को 20 किमी पैदल चाल इवेंट में प्रतिभाग करेंगी।, 2 अगस्त को पारुल चौधरी 5000 मीटर दौड़ के पहले राउंड में रात 9:40 पर भाग लेंगी।, 4 अगस्त को पारुल 3000 मीटर स्टीपल चेज के पहले राउंड में दोपहर 1: 35 मिनट पर इवेंट में भाग लेंगी।, 5 अगस्त को 5000 मीटर दौड़ का फाइनल राउंड होगा।, 6 अगस्त को 3000 मीटर स्टीपल चेज का सेमीफाइनल , 7 अगस्त को सुबह 11 बजे स्टीपल चेज का फाइनल होगा। 7 अगस्त को ही सुबह 11 बजे प्रियंका गोस्वामी वॉक मिक्स रिले इवेंट में प्रतिभाग करेंगी। दोपहर 1:55 पर अन्नू रानी भाला फेंक के पहले राउंड में प्रतिभाग करेंगी। 10 अगस्त को भाला फेंक का फाइनल राउंड होगा।

न्यूज ब्रीफ

शोएब मलिक ने भारतीय टीम से चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने की अपील की

लाहौर । भारतीय क्रिकेट टीम के चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की संभावनएं नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) भारतीय टीम के मुकाबलों को किसी अन्य जगह पर आयोजित करने की मांग करेगा। शाहिद अफरीदी के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भारतीय टीम से पाकिस्तान दौरे पर आने की अपील की है। माना जा रहा है कि दोनो देशों के बीच तनाव को देखते हुए ही सरकार टीम को सुरक्षा कारणों से पाक जाने की अनुमति नहीं देगी। इसी को लेकर पाक खिलाड़ी निराश हैं और भारतीय टीम से दौरे पर आने को कह रहे हैं। अब पूर्व पाक कप्तान शोएब मलिक ने भारतीय टीम से पाकिस्तान आने की अपील करते हुए कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिये। मलिक ने कहा कि पाक ने भारत में हुए एकदिवसीय विश्वकप में भाग लिया था। ऐसे में अब भारतीय टीम की बारी है। साथ ही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी परेशानियां हैं, उसे निजी तौर पर हल करना चाहिए। राजनीति को खेल से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही कहा कि भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पाकिस्तान में नहीं खेले हैं तो उनके लिए यह अच्छा मौका होगा। हम बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम यहां जरूर आएगी। वहीं पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय टीम को मनाने का काम आईसीसी पर छोड़ दिया है। आईसीसी की वार्षिक बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम और प्रारूप पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था। इसमें आगे बताया गया कि पीसीबी ने आईसीसी पर भारत को राजी करने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। पीसीबी ने भारत के सभी मैच लाहौर में रखे हैं, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल भी खेले जाएंगे।

लतीफ ने पंड्या की उपेक्षा पर नाराजगी जतायी

लाहौर । पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने श्रीलंकाई दौरे के लिए हार्दिक पंड्या को भारतीय टी20 टीम का कप्तान नहीं बनाये जाने के फैसले को गलत बताया है। लतीफ ने कहा कि जिस प्रकार का तर्क चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने दिया है। वह केवल बहाने बाजी भर है। अगरकर ने कहा था कि पंड्या को खराब फिटनेस के कारण कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं दी है। अगरकर के इस फैसले से लतीफ को निराशा हुई है। उन्होंने कहा है कि फिटनेस का बहाना देकर हार्दिक को कप्तानी नहीं दी गई। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'उन्होंने पंड्या को सर्टिफिकेट दे दिया है कि वह पूरी तरह फिट नहीं हैं। उनकी फिटनेस को लेकर अब भी कई सवाल हैं पर अगर देखा जाये तो ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जो फिट नहीं हैं लेकिन इसके बाद भी भी वे बहुत अच्छे कप्तान बने हैं। मुझे लगता है कि यह एक बहाना है क्योंकि नये कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम पहले दावेदारी में नहीं था। अगरकर ने कहा था कि फिटनेस एक बड़ी चुनौती थी और हम ऐसा कोई ऐसा खिलाड़ी चाहते थे जो अधिकतर उपलब्ध रहे।' लफीफ से पहले कई और पूर्व क्रिकेटरों ने भी पंड्या की उपेक्षा पर सवाल उठाये थे और कहा था की उन्हें जानबूझकर अलग रखा गया है।

जुबिन से मिली सीख का लाभ उठाएंगे हमारे खिलाड़ी : जयसूर्या

कोलंबो । श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच सनथ जयसूर्या ने कहा है कि राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस निदेशक जुबिन भरूचा से मिली सीख से उनकी टीम भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। साथ ही कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों के नहीं होने से भी उनकी टीम को लाभ होगा। रोहित और विराट ने टी20 विश्वकप के बाद संन्यास ले लिया था। भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी। जयसूर्या ने कहा कि टीम के लिए जुबिन के साथ छह दिन का कैंप रखा गया था। जयसूर्या ने कहा, 'हमने एलपीएल के तुरंत बाद ही ये कैंप शुरू कर दिया था। इस दौरान अधिकतर खिलाड़ी एलपीएल में खेल रहे थे पर इसके बाद भी उन्हें जुबिन के पास भेजा गया। साथ ही कहा कि. हमने उनके साथ लगभग छह दिन काम किया। लीगमें खेलने बाद अन्य क्रिकेटर भी उनके साथ जुड़े और उनके अनुभवों से खिलाड़ियों को लाभ भी हुआ है।' जयसूर्या ने कहा कि भरूचा के साथ सत्र काफी गंभीर रहा और खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिला। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'हमारी तैयारी अच्छी है। टी20 सीरीज शुरू होने से पहले कैंडी में हमारे पास दो दिन और हैं।

सूर्यकुमार की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ जीत से शुरुआत करने उतरेगी भारतीय टीम

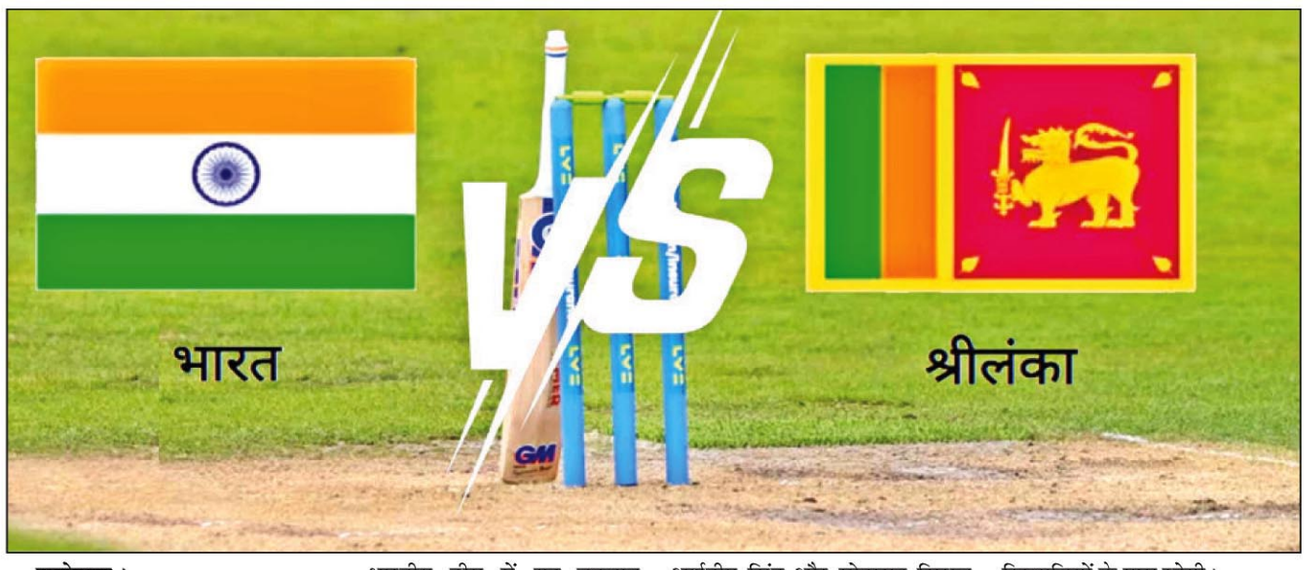

पालेकल ।

भारतीय क्रिकेट टीम नये कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम इस दौरे में श्रीलंका से तीन मैच खेलेगी और गंभीर व सूर्या की जोड़ी का लक्ष्य इसमें टीम को जीत दिलाना रहेगा।

गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह कोच बनाया गया है। गंभीर को अब उनके काम को आगे बढ़ाना होगा। गंभीर को इस दौरे में उनकी मांग के अनुसार टीम दी गयी है। ऐसे में उनकी पहली परीक्षा ये दौरा होगा। इस दौर में सूर्यकुमार को कप्तान बनाया गया है जबकि हार्दिक पंड्या इस पद के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे। इसके अलावा कई युवा खिलाड़ियों को भी अवसर मिला है।

भारतीय टीम में यह बदलाव पिछले महीने विश्व कप जीतने तथा रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आया है। इस सीरीज में उपकप्तानी संभाल रहे शुभमन गिल इसे अपनी जगह पक्की करने के अवसर के रूप में देखेंगे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और यहां तक कि रियान पराग जैसे अन्य खिलाड़ी भी यही चाहेंगे।

अक्षर पटेल टीम में जडेजा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके अलावा भारत के पास हार्दिक, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।

इस दौरे में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और ऐसे में गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज पर रहेगी। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शुभमन, सूर्यकुमार जैसे बल्लेबाजों पर रहेगी। वहीं दूसरी ओर मेजबान श्रीलंकाई टीम की राह भी आसान नहीं है। उसके दो अनुभवी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गये हैं। अब उनकी जगह असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका को टीम में लिया गया है।

श्रीलंकाई टीम इस सीरीज में नये कतान चरिथ असलांका और अंतरिम कोच सनत जयसूर्या के मार्गदर्शन में उतरेगी। मेजबान टीम घरेलू हालातों का लाभ उठाकर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। उसके पास दासुन शनाका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ियों के पास रहेगी।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं:

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज।

श्रीलंका : चरिथ असलांका (कप्तान), दिनेश चांदीमल, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, वानिंदु हसरंगा, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, चामिंडु विक्रमसिंघे, बिनुरा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, डुनिथ वेलालगे।

दूसरे दौर में जोकोविच और नडाल की हो सकती है भिड़ंत, एंडी मरे का बड़ा फैसला, खेलेंगे सिर्फ युगल

पेरिस ।

जोकोविच अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के खिलाफ करेंगे जबकि नडाल का सामना हंगरी के मार्टन फुकसोविक्स से होगा। इन मैचों में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी दूसरे दौर में एक दूसरे का सामना करेंगे।

पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई को होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के दूसरे दौर में राफेल नडाल से भिड़ सकते हैं। वहीं, दो बार के ओलंपिक टेनिस स्वर्ण पदक विजेता एंडी मरे ने पेरिस खेलों की एकल स्पर्धा से हटने का फैसला किया और वह डैन इवांस के साथ केवल युगल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

मैथ्यू एबडेन के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे जोकोविच

जारी किए गए ड्रॉ के अनुसार जोकोविच अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के खिलाफ करेंगे जबकि नडाल का सामना हंगरी के मार्टन फुकसोविक्स से होगा। इन मैचों में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी दूसरे दौर में एक दूसरे का सामना करेंगे।

एंडी मरे ने किया बड़ा एलान

वहीं, इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास का एलान कर चुके एंडी मरे ने एकल स्पर्धा में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन के दिग्गज खिलाड़ी ने कहा, मैंने डैन के साथ युगल स्पर्धा पर ध्यान लगाने के लिए एकल से हटने का फैसला किया है। हमारा अभ्यास शानदार रहा है और हम एक दूसरे के साथ अच्छा खेल रहे हैं।

दो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी एंडी मरे

मरे के हटने की घोषणा ओलंपिक टेनिस स्पर्धा के ड्रा से कुछ देर पहले ही हुई। मरे ने लंदन 2012 और रियो डि जिनेरियो 2016 की एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीते थे जिससे वह दो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं।

श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में एक अहम रिकार्ड बना सकते हैं विराट

मुम्बई ।

श्रीलंका के खिलाफ अगले माह होने वाली एकदिवसीय क्रिकेट सीरीज में भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विराट इस सीरीज के दौरान ऐसा रिकॉर्ड बना सकते है जो किसी अन्य क्रिकेटर के लिए तोड़ना असंभव की तरह रहेगा। विराट इस सीरीज में 27,000 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं।

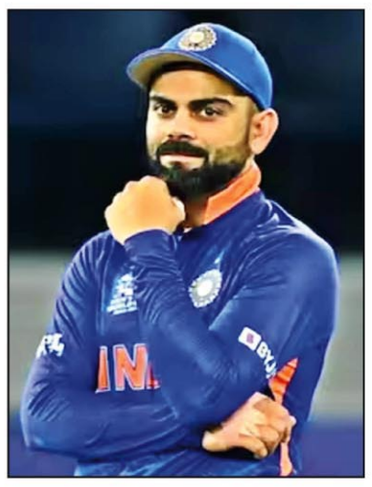

विराट के नाम अभी 53.55 की औसत से 26,884 रन हैं। ऐसे में अगर वह श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में 116 रन बनाते हैं तो उनके तीनों प्रारुपों को मिलाकर कुल 27 हजार रन हो जाएंगे। यह वो आंकड़ा है, जो अब तक केवल तीन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 34357, कुमार संगकारा 28016 और रिकी पोंटिंग 27483 ही हासिल कर पाये हैं।

आज के दौर के क्रिकेटरों की बात करें तो विराट के अलावा एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने 20,000 रन बनाए हों। वर्तमान समय के क्रिकेटरों में विराट कोहली के बाद जो रूट 19,355 रनों के साथ दूसरे और रोहित 19,077 रनों के साथ ही तीसरे नंबर पर हैं। रूट 33 साल के हैं जबकि रोहित की उम्र 37 साल है। अब अगर ये दोनों खिलाड़ी 40 साल की उम्र तक खेलें तो जो रूट के लिए तो यह संभव है कि वे 27 हजार रन बना लें। रोहित के लिए भी ये काफी कठिन है। रोहित ने अब तक कुल 480 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 43.25 की औसत से 19,077 रन बनाए हैं। उन्हें 27 हजार रन का आंकड़ा हासिल करने के लिए 7923 रन और बनाने होंगे। रोहित को 27 हजार रन तक पहुंचने में करीब चार साल लगेंगे। उनके 40 साल की उम्र तक खेलने की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में वह इस रिकार्ड तक नहीं पहुंच सकते।

फलस्तीन ओलंपिक टीम का पेरिस पहुंचने पर शानदार स्वागत, तोहफों और तालियों से किया गया वेलकम

पेरिस ।

फलस्तीन के ओलंपिक दल का यहां पहुंचने पर लोगों ने तालियों और तोहफों के साथ स्वागत किया और तोहफों में खाने का सामान और गुलाब के फूल शामिल थे। पेरिस हवाई अड्डे से बाहर निकलकर फलस्तीन के खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब तक 39000 फलस्तीनियों की जान ले चुके इजराइल-हमास युद्ध के बीच उनकी मौजूदगी संकेत की तरह होगी।

खिलाड़ियों, फ्रांस के समर्थकों और राजनीतिज्ञों ने यूरोपीय देशों से फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। कइयों ने ओलंपिक में इजराइली खिलाड़ियों के खेलने पर नाराजगी जताई है जिन्होंने इजराइल पर युद्धापराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए हैं। सउदी अरब में जन्मे 24 वर्ष के फलस्तीनी तैराक याजान अल बवाब ने कहा, फ्रांस फलस्तीन को एक राष्ट्र नहीं मानता इसलिये मैं यहां फलस्तीन का झंडा लहराने आया हूं। हमारे साथ इंसान की तरह बर्ताव नहीं होता इसलिए हम यहां खेलने आए हैं ताकि लोग हमें बराबरी का समझे।

खेल महाकुंभ ओलिंपिक गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। चार साल में एक बार होने वाले गेम्स इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे।

पेरिस ओलिंपिक में 32 खेलों के 329 स्वर्ण पदक दांव पर लगे हैं। इस बार 206 एसोसिएशन और देशों के 10,500 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। भारत के 117 खिलाड़ी 16 खेलों में पदक के लिए दांव लगाते दिखेंगे। पेरिस की सीन नदी पर ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसमें सभी देश और एथलीट्स हिस्सा लेंगे। 129 साल के ओलिंपिक इतिहास में ओपनिंग सेरेमनी पहली बार स्टेडियम के अंदर नहीं, बाहर होगी। परेड छह किमी. लंबी होगी। सेरेमनी में 120 से ज्यादा देशों के नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। फ्रांस ने 2024 ओलिंपिक का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन रखा है। 27 जुलाई से मेडल इवेंट शुरू हो जाएंगे। पेरिस ओलिंपिक में ब्रेकडांस इवेंट का डेब्यू होगा, यह इस बार के गेम्स में शामिल इकलौता नया खेल है।

ये स्टार शटलर जीतेंगे पदक..., दीपिका के पिता और बैडमिंटन लीजेंड प्रकाश पादुकोण की भविष्यवाणी

नई दिल्ली।

दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और शीर्ष शटलर पीवी सिंधू के मेंटर प्रकाश पादुकोण का मानना है कि भारत के पास पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में तीन पदक जीतने का मजबूत मौका है और इनमें सिंधू के लिए पदकों की हैट्रिक भी शामिल है। भारत ने सात सदस्यीय बैडमिंटन टीम भेजी है जिसमें सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी और दो ओलंपिक पदक विजेता सिंधू शामिल हैं।

पादुकोण ने कहा कि सिंधू पेरिस में अपने लगातार तीसरे ओलंपिक पदक के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, हम अच्छे प्रैक्टिस की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। सिंधू ने ओलंपिक के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है। हालांकि, इस स्तर पर कुछ निश्चित या प्रतिबद्ध नहीं हो सकता है। उनकी तैयारियां अच्छी चल रही हैं और वह अभ्यास सत्र में अच्छा खेल रही हैं। इसलिए तैयारियों के मामले में सब कुछ बहुत अच्छा रहा है।

अनुभवी शटलर, पूर्व ऑल-इंग्लैंड चैंपियन और अपने सुनहरे दिनों में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी रहे प्रकाश ने बताया कि वह कोर्ट पर सिंधू की रणनीति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उन्होंने उनके मार्गदर्शन में बहुत सुधार भी किया है। प्रकाश ने कहा, मैं कोर्ट पर रणनीति सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। इस पर कि सिंधू को कब किस स्ट्रोक का उपयोग करना है और दिमाग के साथ कैसे खेलना है। लगभग नौ महीने पहले वह लगातार कोचिंग परिवर्तन के कारण आत्मविश्वास में थोड़ा कमजोर पड़ गई थीं और यह पहचानने में सक्षम नहीं थीं कि उनके साथ क्या गलत हो रहा था।

प्रकाश ने कहा, हमने उनकी मानसिक मजबूती और रणनीति पर काम किया है और सुनिश्चित किया है कि वह सही स्ट्रोक का बेहतर इस्तेमाल करें। हमने गलतियों में कटौती करने और प्रतिशत बैडमिंटन खेलने की कोशिश की है। यह जानते हुए कि कब विपक्षी खिलाड़ी पर आक्रमण करना है या कब बचाव करना है और सुरक्षित खेलना है। हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगाया जाना बाकी है कि क्या वह ओलंपिक के दौरान उस फॉर्म को दोहरा सकती हैं।

सिंधू के इस साल अब तक कोई खिताब जीतने में नाकाम रहने के बावजूद प्रकाश को लगता है कि मुश्किल परिस्थितियों में चमकने की उनकी क्षमता और ओलंपिक में भारत की सबसे सफल महिला खिलाड़ी होना उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करेगी। सिंधू दो ओलंपिक पदक, 2016 में रियो में एक रजत और टोक्यो में कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।

धीमी गति से फैलता है कार्सिनॉइड ट्यूमर

फेफड़े के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स को धीमी गति का कैंसर कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास बहुत ही धीमी गति से होता है और अन्य ट्यूमर्स की अपेक्षा शरीर के अन्य भागों में इसके फैलने की आशंका भी बहुत कम होती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी इसका विकास और फैलाव अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है।

अधिकांश कार्सिनॉइड ट्यूमर्स की शुरूआत छोटी आंत में होती है, लेकिन लगभग 25 प्रतिशत फेफड़ों में शुरू होते है। कार्सिनॉइड ट्यूमर्स फेफड़ों के मध्य से शुरू होते हैं। कुछ कार्सिनॉइड ट्यूमर्स विशेषकर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाईन ट्रैक्ट या अपेंडिक्स में पनपते हैं वे ऐसे हार्मोन होते हैं जिनसे अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं। जबकि फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स में कभी भी ऐसा नही होता हैं। हालांकि यह घातक होने की क्षमता रखता है लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ने के कारण कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होने पर भी लोग आमतौर पर कई वर्षो तक जीवित रहते है और कभी-कभी तो एक सामान्य जीवन जीते हैं।

कार्सिनॉइड ट्यूमर्स के प्रकार–फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स के दो प्रकार होते हैं- विशिष्ट कार्सिनॉइड ट्यूमर्स और असामान्य कार्सिनॉइड ट्यूमर्स।

असामान्य कार्सिनॉइड ट्यूमर्स

विशिष्ट कार्सिनॉइड ट्यूमर्स की अपेक्षा असामान्य कार्सिनॉइड ट्यूमर्स लगभग नौ गुना ज्यादा पाए जाते हैं, इनकी फेफड़ों तक फैलने की सम्भावना बहुत कम होती है।

विशिष्ट कार्सिनॉइड ट्यूमर्स

विशिष्ट प्रकार के कार्सिनॉइड बहुत दुर्लभ होते हैं। वह असामान्य की तुलना में तेजी से बढ़ते है और इनके फेफड़ों से बाहर फैलने के ज्यादा मौके होते हैं। फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स अधिकतर 45 से 55 वर्ष की आयु के पुरूषों और महिलाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स को वर्गीकृत करने का एक और रास्ता भी है कि उसे उनके स्थान द्वारा वर्गीकृत किया जाए। केन्द्रीय कार्सिनॉइड फेफड़ों के बीच निकट बड़े वायुमार्ग की दीवारों में पाए जाते हैं। परिधीय कार्सिनॉइड संकरा वायु मार्ग में फेफड़ों के किनारों के करीब पाए जाते हैं। दोनों केंद्रीय और परिधीय कार्सिनॉइड आमतौर पर विशिष्ट कार्सिनॉइड हैं।

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स ट्यूमर का एक असामान्य प्रकार है जो फेफड़ों में शुरू होता हैं और अन्य प्रकार के फेफड़ों के कैंसर की तुलना में धीमी वृद्धि करते हैं। फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं जो न्यूरोएन्डोक्राइन कोशिका कहलाती हैं।

न्यूरोएन्डोक्राइन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से कार्सिनॉइड ट्यूमर

ज्यादातर कार्सिनॉइड ट्यूमर छोटी आंत से आरंभ होते हैं लेकिन कैंसराभ फेफड़ों ट्यूमर सभी कारसीनोइड ट्यूमर के बारे में 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्सिनॉइड फेफड़ों ट्यूमर में 1%-6% सभी फेफड़ों के ट्यूमर शामिल हैं।

यह जानने के बाद कभी नहीं चटकाएंगे उंगलियां

हमारी हड्डियां लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसे जोड़ कहते हैं जब हम उंगलियां चटकाते हैं और इस तरह हड्डियों को एक दूसरे से दूर खींचते हैं। तो उंगलियों के जोड़ों में एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है, ऐसे में द्रव में बुलबुले बन जाते हैं। जब हम जोड़ों को काफी अधिक खींचते हैं तो यह बुलबुले फूट जाते हैं और हड्डियों के जोड़ पर मौजूद ऊतक नष्ट भी हो सकते हैं।

जान का खतरा बन सकता है ट्रैफिक

खोजकर्ताओं के मुताबिक, ट्रैफिक जाम में बार-बार फंसने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप एक घंटे से ज्यादा ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जहरीली गैस बनाता है, जो कि कि घर में बैठे व्यक्ति की तुलना में ट्रैफिक में फंसे लोगों को कई गुना अधिक प्रभावित करता है।

लेसिक आई सर्जरी के फायदे और नुकसान

अन्य सर्जरी की तुलना में लेसिक सर्जरी कम खतरनाक है । यह आसान है और मात्र 30 मिनट में ही हो जाती है। इसे एक बार कराने के बाद दोबारा नहीं करा सकते हैं।

आंखें कुदरत की ओर से दी गई सबसे कीमती उपहार हैं। ये जितनी कीमती हैं, उतनी ही संवेदनशील भी हैं। इसलिए तो लोग आंखों का विशेष ख्याल रखते हैं और थोड़ा भी सरदर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाते हैं। पहले लोग आंखों की समस्या से निजात पाने के लिए चश्मा पहनते थे। लेकिन चश्मा एक बार चढ़ गया तो जिंदगी भर लगाना पड़ता है। लेकिन विकसित होती तकनीक ने आंखों के उपचार को आसान कर दिया है। आजकल डॉक्टर चश्मा लगाने वाले को लेसिक सर्जरी करने की हिदायत देते हैं और लोग लेसिक सर्जरी का फायदा भी उठा रहे हैं। लेसिक सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। आइए इस लेख में लेसिक सर्जरी के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं।

आंखें अनमोल हैं, इसलिए इससे जुड़ी किसी भी तरह की सर्जरी कराने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें।

आंखें कुदरत की ओर से दी गई सबसे कीमती उपहार हैं। ये जितनी कीमती हैं, उतनी ही संवेदनशील भी हैं। इसलिए तो लोग आंखों का विशेष ख्याल रखते हैं और थोड़ा भी सरदर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाते हैं। पहले लोग आंखों की समस्या से निजात पाने के लिए चश्मा पहनते थे।

लेकिन चश्मा एक बार चढ़ गया तो जिंदगी भर लगाना पड़ता है। लेकिन विकसित होती तकनीक ने आंखों के उपचार को आसान कर दिया है। आजकल डॉक्टर चश्मा लगाने वाले को लेसिक सर्जरी करने की हिदायत देते हैं और लोग लेसिक सर्जरी का फायदा भी उठा रहे हैं। लेसिक सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। आइए इस लेख में लेसिक सर्जरी के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं।

क्या है लेसिक सर्जरी

जो लोग चश्मा पहनते हैं और जिनका पावर -1 से -10 के बीच है, उन्हें तुरंत आंखों की लेसिक सर्जरी करवानी चाहिए। जांच में देख लें कि आपके कॉर्निया की थिकनेस कैसी है। जितनी अधिक थिकनेस होगी इस सर्जरी का फायदा उतना अधिक होगा। साथ ही लेसिक सर्जरी की सबसे अच्छी बात है कि ये अन्य दूसरी सर्जरी की तुलना में ज्यादा आसान और बेहतर है। यह सस्ती होती है और इसमें कॉर्निया को नुकसान पहुंचने का खतरा न के बराबर होता है। जबकि दूसरी सर्जरी में कॉर्निया पर खतरा ज्यादा रहता है।

लेसिक सर्जरी के फायदे

- लेसिक सर्जरी 30 मिनट या उससे कम समय में हो जाती है। साथ ही यह सर्जरी आंखों के लिए काफी प्रभावी और कारगार मानी गई है, जिस कारण अधिकतर लोग आंखों के लिए लेसिक सर्जरी करने की हिदायत देते हैं।
- 92-98% लोग आंखों की समस्या से निजात पाने के लिए लेसिक सर्जरी का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि ये आंखों की दृष्टि के लिए काफी फायदेमंद होती है और किसी भी अन्य सर्जरी की तुलना में आसान और किफायती होती है।
- लेसिक सर्जरी दृष्टि से जुड़ी सभी समस्याओं और खतरों को काफी हद तक दूर कर देती है।

लेसिक सर्जरी के नुकसान

- लेसिक सर्जरी आंखों के सबसे संवेदनशील हिस्से में की जाती है और इसे दोबारा नहीं किया जा सकता है।
- लेसिक सर्जरी के कुछ दिनों के बाद ही लोगों को पढ़ने के लिए तो चश्मे की जरूरत पड़ती ही है।
- सबसे बड़ा खतरा लेसिक सर्जरी का ये है कि, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा नहीं होता। मतलब की इस सर्जरी के दौरान अगर आपकी आंखों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी न डॉक्टर की और न इंश्योरेंस विभाग की होगी।
- आंखें अनमोल हैं, इसलिए इससे जुड़ी किसी भी तरह की सर्जरी कराने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें।

जहरीली मकड़ी काटने पर करें ये घरेलु उपाय

घर की नियमित सफाई नहीं होती है तो मकड़ी के जालें दिखने लगते हैं। सामान्य मकड़ी द्वारा काटा जाना हमारे लिए इतना घातक नहीं होता। लेकिन कुछ खास प्रकार की मकड़ियां जैसे ब्लैक विडो, या ब्राउन स्पाइडर इनका काटना खतरनाक भी हो सकता है। ये मकड़ियां काफी जहरीली होती हैं। इन मकड़ियों के काटने पर जब यह अपना जहर काटे गए हिस्से में छोड़ देती है तो वहां सूजन, तेज खुजली, दर्द, लाल हो जाना और जलन जैसे लक्षण उभर कर सामने आते हैं। ऐसे में हम कुछ घरेलु उपचारों द्वारा इस परेशानी से निजात पा सकते हैं-

सबसे पहले काटे गए स्थान को अच्छे से धो लें और फिर बर्फ से सिकाई करें। इस से न सिर्फ जलन और दर्द में राहत मिलेगी बल्कि सूजन भी कम होगी। याद रहे कि बर्फ को सीधे उस जगह पर न रखें नही तो जलन और तेज हो सकती है। बेकिंग सोडा एक या दो चम्मच लेकर पानी के साथ मिलकर पेस्ट बना लें और काटने के स्थान पर लगाएं। इस विधि से काटे गए स्थान पर जल्दी राहत मिल जाएगी।

यदि एक बार में काम न चलें तो इस विधि को कुछ समय बाद दोबारा भी दोहराया जा सकता है। नमक इस जहर को उतारने में बहुत उपयोगी औषधि है, यह मकड़ी ही नहीं अनेकों विषाक्त कीड़ों के काटने पर राहत दे सकता है। इसके लिए एक छोटे चम्मच नमक की लेकर इसे काटे गए स्थान पर किसी कपड़े की सहायता से बांध दें। इसे तब तक बंधा रहने देना चाहिए जब तक कि सूजन कम न होने लगे।

प्राकृतिक उपायों से दूर करें होठों का कालापन

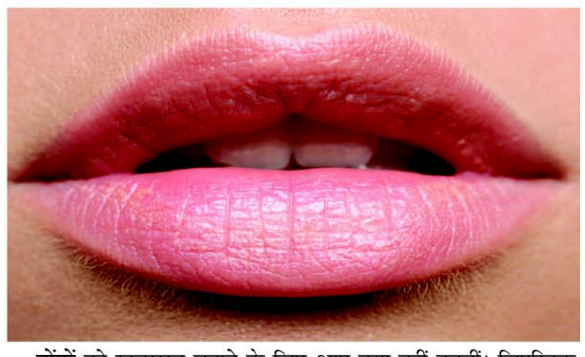

होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या नहीं करतीं। लिपस्टिक, लिप बाम, माश्चराइजर और ना जाने क्या-क्या। लेकिन, होंठों पर लगाए जाने वाले कई उत्पाद वास्तव में उन्हें खूबसूरत बनाने के बजाय लंबे समय में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप भी अपने होठों के फटने या कालेपन से परेशान हैं तो इस लेख में बताए गए उपायों को अपनाकर अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

कोको बटर

दो बड़े चम्मच कोको बटर, आधा छोटा चम्मच मधु वैक्स लीजिए। उबलते पानी पर एक बर्तन में वैक्स डालकर पिघला दीजिए। इसमें कोको बटर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद ब्रश की मदद से होंठों पर लगाइए। इससे होंठ मुलायम होंगे और उनका कालापन दूर हो जाएगा।

दूध की मलाई

होंठों से रूखापन हटाने के लिए थोडी सी मलाई में चुटकी भर हल्दी? मिलाकर नियमित रूप से धीरे-धीरे होठों पर मालिश करें। आप देखेंगे कि इस घरेलू उपाय से कुछ ही दिनों में आपके होठ मुलायम और गुलाबी होने लगेंगे।

गुलाब की पंखुडियां

होंठों के कालेपन को दूर करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके नियमित इस्तेमाल से होठों का रंग हल्का गुलाबी और चमकदार हो जाएगा इसके लिए गुलाब की पंखुडियों को पीसकर उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर इस घोल को रोज रात को सोते समय अपने होंठों पर लगाकर सो जाएं और सुबह धो लें।

- **नींबू**: क्या आप जानते है होंठों को कालापन नींबू से भी दूर हो सकता है। इसके लिए आप निचोड़े हुए नींबू को अपने होठों पर सुबह और शाम को रगड़ें।
- **केसर**:होंठों का कालापन दूर करने के लिए कच्चे दूध में केसर पीसकर होंठों पर मलें। इसके इस्तेमाल से होंठों का कालापन तो दूर होता ही है साथ ही वे पहले से अधिक आकर्षक बनने लगते हैं।
- **शहद**: शहद के इसॅतेमाल से कुछ ही दिनों में आपके होंठ चमकदार और मुलायम हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा-सा शहद अपनी उंगली में लेकर धीरे-धीरे अपने होंठों पर मलें या फिर शहद में थोड़ा सा सुहागा मिलाकर अपने होंठों पर लगाएं। ऐसा एक दिन में दो बार करें फिर देखें इसका असर।
- **अंडे की जर्दी**: अंडा खाना आपकी सेहत के लिए तो अच्छा होता ही हैं, लेकिन क्या आप जानते है यह होंठों का कालापन दूर करने में भी सहायक होता है। होंठों पर अंडे की जर्दी का लेप लगाने से होंठों की लालिमा बरकरार रहती है।
- **जैतून का तेल**: यदि होंठ पूरी तरह से फट चुके हैं और उनमें कालापन भी आ रहा है तो जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल और वैसलीन मिलाकर दिन में तीन या चार बार फटे होंठों पर लगाने से फायदा होता है। इनका लेप होंठों पर 4-5 दिन लगातार लगाने से होठों की दरारें भी भरने लगती हैं और होंठ हल्के गुलाबी भी होने लगते हैं।
- **चुकंदर**: चुकंदर को ब्लड बनाने वाली मशीन भी कहते है। चुकंदर होंठ के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। चुकंदर को काटकर उसके टुकड़े को होंठों पर लगाने से होठ गुलाबी व चमकदार बनते हैं।

कैंसर, डायबिटीज और मोटापे का दुश्मन है यह फल

आलूबुखारे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कहते हैं कि एक कटोरा भर के फलों में जितने पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं उतने ही एक आलूबुखारे में होते हैं। आलूबुखारा कई पोषक तत्वों और मिनरल्स से भरपूर होता है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम और फाइबर मौजूद होते हैं। आलूबुखारा खाने से कैंसर, डायबिटीज और मोटापे संबंधी कई गंभीर रोगों में आराम मिलता है।

> आलूबुखारा कई पोषक तत्वों और मिनरल्स से भरपूर होता है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम और फाइबर मौजूद होते हैं।

अस्थिभंग की आशंका नहीं

एक शोध के अनुसार रोजाना आलूबुखारा खाने से अस्थिभंग यानी हड्डियों की क्षति की आशंका को कम किया जा सकता है। आयु बढ़ने के साथ ही हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सूखा आलूबुखारा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। एक नए अध्ययन में पता चला है कि आलूबुखारा हड्डी टूटने से बचा सकता है। अध्ययन के अनुसार यदि महिलाएं रजोनिवृत्ति के बाद इस फल का सेवन करें तो वे स्वयं को ओस्टियोपोरेसिस और हड्डी टूटने से बचा सकती हैं। अध्ययन में पता चला है कि प्रतिदिन 10 आलूबुखारा खाने से अस्थिभंग की आशंका को कम किया जा सकता है। आयु बढने के साथ ही हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। सूखा आलूबुखारा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए सूखे अंजीर, सूखे स्ट्रॉबेरी, सूखे सेब और किशमिश से अधिक लाभकारी है।

इन बातों का रखें ध्यान

आलूबुखारे में आयरन होता है जो एनीमिया (रक्त की कमी) के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके कई तरह के पोषक तत्व शरीर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसे खा सकता है लेकिन जिन्हें गले में खराश, खांसी और जुकाम की समस्या हो वे इन्हें खाने से परहेज करें। एक दिन में इनकी 100 से 150 ग्राम मात्रा खाई जा सकती है। जहां तक संभव हो इन्हें इनके मौसम में ही खाना चाहिए।

इसके हैं कई लाभ

- आलूबुखारे में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इससे पेट संबंधी समस्या दूर होकर पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। इसके सेवन से पेट में भारीपन नहीं होता है और आंतों को भी आराम मिलता है। आलूबुखारे में फैट की मात्रा कम होती है जिससे मोटापा नहीं बढ़ता और वजन नियंत्रण में रहता है।
- इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में होता हैं।
- विटामिन-ए, आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
- आलूबुखारे में पोषक फाइबर जिया एक्साथिन होता है जो आंखों के रेटिना को मजबूत बनाता है।
- आलूबुखारा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो शरीर में बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखता है।
- यह बालों से संबंधित समस्याओं में राहत दिलवाने में मदद करता है।

रेसिपी

मिलानो मिनेस्ट्रान

सामग्री

1/4 कप गेहूं से बना पैने, 2 टी-स्पून सूखा ऑरेगानो, 1 1/2 टी-स्पून तेल, 2 टेबल-स्पून बारीक कटे हुए प्याज़, 2 तेजपत्ता, 1 1/2 कप बारीख कटे हुए गाजर, 2 टेबल-स्पून बारीक कटी हुई फूलगोभी, 2 टेबल-स्पून हरे मटर, 3/4 कप छिले और बारीक कटे हुए आलू, 3 टेबल-स्पून बारीक कटी हुई पत्तागोभी, 1 टेबल-स्पून कोर्नफ्लॉर , 1/2 कप पानी में घोला हुआ, 2 टेबल-स्पून कटे हुए टमाटर, 4 टेबल-स्पून टमाटर की प्यूरी, नमक और ताज़ी पीसी काली मिर्च स्वादअनुसार, **सजाने के लिए,**2 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ पार्सले,

विधि

एक गहरे नॉन-स्टिक पैन में तेल गरम करें, प्याज़ और तेजपत्ता डालकर मध्यम आंच पर 30 सेकन्ड तक भूनें। गाजर, फूलगोभी, हरे मटर और 5 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर बीच-बीच में हिलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएं। आलू, पत्तागोभी और गेहूं से बने पैने डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर 7 से 8 मिनट या सब्ज़ी के नरम होने तक, बीच-बीच में हिलाते हुए पका लें। कोर्नफ्लॉर-पानी का मिश्रण, टमाटर, टमाटर की प्यूरी, ऑरेगानो, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर लगातार हिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएं। पार्सले से सजाकर गरमा गरम परोसें।

दही सौंफीयानी टिक्की

सामग्री

1 कप चक्का दही, 1/2 कप कसा हुआ पनीर, 3 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टी-स्पून कटा हुआ लहसुन, एक चुटकी शक्कर, नमक स्वादअनुसार, 2 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ पुदिना, 1 टी-स्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबल-स्पून घी, 2 टेबल-स्पून भूनी हुई चना दाल का पाउडर, 2 टी-स्पून कोर्नफ्लॉर, तेल , तलने के लिए

विधि

दही, पनीर, हरी मिर्च, लहसुन, शक्कर, नमक, धनिया, पुदिना और सौंफ पाउडर को बाउल में अच्छी तरह मिला लें। एक तरफ रख दें। पैन में घी गरम करें, भुनी हुई चना दाल का पाउडर, दही का मिश्रण और कोर्नफ्लॉर डालकर मिश्रण के गाढ़े होने तक या पैन से अलग होने तक पका लें। ठंडा करने एक तरफ रख दें। मिश्रण को 8 बराबर भाग में बांटकर, प्रत्येक भाग के गोल चपटी टिक्की बना लें। मध्यम आंच पर कढ़ाई में तेल गरम करें और टिक्की को दोनो तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। तेल सोखने वाले कागज़ में निकालकर गरमा गरम परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम** ● **फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**